With regard to planting of a bomb in Parliament Street Post Office, I would like to say that on August 23, 1983 a bag which was suspected to contain an explosive was found lying in the main hall of the Parliament Street Post Office by a Chowkidar of the Post Office. A hand written letter in Punjabi purporting to be from Dal Khalsa containing usual threats and warnings was found with the bag. The police and explosive experts reached the scene immediately. It was found to contain gun powder and small nails. The experts have stated that it could not have exploded on its own. A case under Section 4 of the Explosives Substances Act has been registered and is under investigation. Of late there has been only one more case, *i. e.* planting of an explosive device in Mohan Singh Place on August 13, 1983. This was found to be a cracker which could not have caused any damage or serious injury. The case is under investigation.

17.04 hrs

DISCUSSION ON STATEMENT MADE BY MINISTER OF FINANCE *RE* : PRICE SITUATION

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up Discussion under Rule 193. Shrimati Pramila Dandavate. Discussion under Rule 193.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Today we are starting the discussion at 5 o'clock. I would like every Member whose name is here, must participate and anyhow, we will have to fix the time for the debate, how far we should sit and when the Minister would reply. Therefore we have to make it clear and then only we can start the discussion.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have not asked you to stand up and speak.

I have chalked out a programme. The mover will take 15 minutes, the bigger parties will take ten minutes and the smaller parties will take five minutes each. The Minister will reply at 7.45 p.m. Now Shrimati Pramila Dandavate.

(*Interruptions*)

SHRI MANI RAM BAGRI (Hissar) : Point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am sorry. What is your point of order ? Under what rule ?

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Under Rule 376.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Time is being wasted. If you are going to do anything in a clandestine matter or ask for some clarification, I will not allow.

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने इस्तीफा देते वक्त सोचा कि क्या करने जा रहे हो और क्या नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am sorry. There is no point of order. There is no point of order. Now, discussion. I am sorry.

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। गृह मंत्री जी से व्यान के लिए इसलिए कहा गया था कि देश के अन्दर जो बिगड़ते हुए हालात हैं।

···(व्यवधान)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not record.

(*Interruptions*)**

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात सुनिए। सारे सदन की अपील को जब निरंकारियों ने माना और मानकर···(व्यवधान)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : When a *suo moto* statement has been made no clarification can be sought. Time is being wasted.

**Not recorded.

Some times an important discussion takes place. All of you must co-operate.

(*Interruptions*)

श्री मनोराम बागड़ी : उपाध्यक्ष जी, पंजाब जल रहा है। आप मजाक समझ रहे हैं। लोगों की जिन्दगी जा रही है।···(**व्यवधान**)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shrimati Pramila Dandavate. The time allotted to you is fifteen minutes, Madam.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : ता० 18 को अर्थ-मंत्री ने एक निवेदन सदन के सामने रखा था। मैं इस समय एक गृहणि के नाते बोलने वाली हूं- मुझे ऐसा महसूस होता है, हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं—वे बाजार में नहीं जाते हैं, इसलिये उन को चीजों की कीमतों का ज्ञान नहीं होता है···

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East) : Including Madhu Dandavate ?

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Yes, including Dandavate.

उन से यदि पूछा जाय कि डालडा की कीमत क्या है, तेल की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है—सच्चे मायनों में उन को कुछ भी मालूम नहीं होता है। लेकिन मैं ये सारी चीजें खरीदती हूं क्योंकि मुझे घर चलाना पड़ता है···

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Instead of attacking the Government, she is attacking me!

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : इसलिये जब पहली बार मुझे सदन में आप का भाषण सुनने को मिला तो मेरा क्या रिएक्शन था···

SHRI RAM SINGH YADAV (Alwar) : Then perhaps male Members may not be given an opportunity.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मुझे ऐसा लगता था कि आज की सरकार जनता की चोटों पर नमक छिड़क रही है। आप का यह कहना कि प्राइस राइज ज्यादा नहीं हुई है, केवल 2.5 परसेन्ट होलसैल प्राइस इण्डैक्स बढ़ गया है और कन्ज्यूयर प्राइस इण्डैक्स 6.5 परसैन्ट बढ़ गया है, यह बहुत माडरेट है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन जो बहन घर को चलाती है उनको पता है कि पिछले तीन सालों में दाम कितने बढ़े हैं, उनको घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। जिनके घर में दो बार खाना पकता था आज नहीं पक सकता है, उनकी आज क्या हालत हो गई है, जिन को चोट पड़ती है सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। आज का बजट तो एक तमाशा बन गया है···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप श्रीमती प्रणव मुखर्जी से बोलिये।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : पता नहीं प्रणब मुखर्जी की पत्नि बाजार जाती भी हैं या नहीं। अगर जाती होंगी तो उनको भी आप का भाषण सुन कर मुझ जैसा ही गुस्सा आया होगा। सच्चे मायनों में पिछले तीन सालों में चीजों के दाम इतने बढ़े हैं कि एक मध्यम वर्ग की गृहणी के लिये घर चलाना आज मुश्किल हो गया है।

आज इस प्राइस राइज के जो कारण हैं—उन में पहला बहुत बड़ा कारण है—काला पैसा। काले पैसे का विस्तार जगह-जगह बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरा कारण - -आप का डेफिसिट फाइनेन्सिंग बढ़ रहा है। तीसरा कारण—आज अनप्रोडक्टिव एक्सपेण्डिचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चौथा कारण—आप मनी-सप्लाई की बात बहुत ज्यादा कहते हैं लेकिन आज तक उस पर कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं। पांचवा कारण—इनएफिशियेन्ट पब्लिक एण्ड प्राइवेट सैक्टर है। ये लोग अपना पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से इनका पूरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और प्राइसेज बढ़ती जा रही हैं। छठा कारण— ब्लैक मार्केटिंग है। टैडर्स में जो एन्टी सोशल एलीमेंन्ट्स हैं वे आर्टीफिशियल स्केअरसिटी पैदा करते हैं जिससे अपना माल मंहगे दामों पर बेच सकें।

हम ने अभी पिछले दिनों एक सवाल पूछा था—जब चीजों के दाम गिर जाते हैं, तो ट्रेडर्स वैगनों से अपने माल को नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि वैगनों का इस्तेमाल गोदाम की तरह से करते हैं। रेलवे मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि इस तरह से भी होता है, जबकि कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के माल को आक्शन किया जा सकता है।

आप कहते हैं कि दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमें तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। 23 अगस्त को जो प्राइसेज अखबार में आई हैं मैं उन्हीं के आधार पर आपको बतलाना चाहती हूं कि होलसैल प्राइस इण्डैक्स कितना बढ़ा है। उनके मुताबिक 6 अगस्त को रेट आफ इन्फलेशन 6.9 परसेन्ट था। फूड आर्टीकल्ज का 10.9 परसेन्ट, फूड ग्रेन्ज का 11.9 परसेन्ट, सीरल्ज का 13 परसेन्ट, और होलसैल प्राइस इण्डेक्स 314.3 दिया है। जबकि यह जनवरी, 1982 में 279 था, जनवरी 1983 में 293 था, अप्रैल, 1983 में 298.4 था और 6 अगस्त, 1983 को 314.3 बन गया।

इस का मतलब यह है कि 14 पर सेन्ट इन्क्रीज हो रहा है। आप 1980 में सत्ता में आ गये थे और उस समय से अगर आप कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स को देखें, तो आप को पता ही है कि अब तक कुल मिला कर प्राइसेज 150 परसेन्ट बढ़ी हैं और उसका असर हम लोगों के बजट पर पड़ा है। मैं और ज्यादा डिटेल्स इस बारे में आपके सामने नहीं रखती हूं लेकिन एक बात यह अवश्य कहना चाहती हूं कि व्होलसेल प्राइसेज का रिफ्लेक्शन कन्ज्यूमर प्राइसेज पर नहीं होता है। आप ने भी यह मंजूर किया है कि नहीं होता है और उसका कारण जैसा कि मैंने पहले कहा है, एक तो यह है कि प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर के बीच में जो मिडिलमैन है, वह मैनीयुलेशन करता है। यह एक कारण है और इसके साथ साथ हमारे करप्ट आफीसर्स भी एक कारण हैं जोकि लाइसेन्सेज के लिए खुले तौर पर नहीं बल्कि अन्डरहैंड डीलिंग करके पैसा ले लेते हैं। इस तरह की कमीशन एजेन्ट कम्पनियां बनी हुई हैं और पैसा देकर काम हो जाता है, जिसका असर कन्ज्यूमर पर पड़ता है। इसलिए प्राइसेज बढ़ने का एक कारण यह भी है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि रथ कमेटी ने कहा था कि जो कन्ज्यूमर इन्डेक्स है, उसमे और चीजें भी, जो कि कन्ज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, जोड़नी चाहिए लेकिन उसके बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं यह सदन को बताना चाहती हूं कि आल इन्डिया प्राइस इन्डेक्स जो मई 1982 में 462 था, वह मई 1983 में बढ़कर 521 हो गया। और जुलाई 1983 में वह 543 हो गया। इस तरह से मई 1982 से मई 1983 के बीच में वह 12.8 परसेन्ट बढ़ा है। इसी प्रकार कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स भी बढ़ रहा है।

ये जो प्राइसेज बढ़ती रही है, इसका एक और कारण मैं बताना चाहती हूं। जब आप बजट पेश करते हैं, तो बजट पेश करते समय जो एक्चुअली बजट के टाइम पर आप टैक्स लगाते हैं, उससे पहले और बाद में आप एक्जीक्यूटिव आर्डस से चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। 1981-82 के बजट के पहले आपने पहले 2500 करोड़ रुपये के चीजों के दाम बढ़ा दिए एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से और बजट के बाद 2600 करोड़ रुपये के चीजों के दाम बढ़ा दिये। इस तरह से आम बजट के बाद आपने 5400 करोड़ रुपये के टैक्स लोगों पर दाम बढ़ा कर लगा दिए। यह काम आप लगातार कर रहे हैं और हर साल ऐसे ही चलता रहता है। एक तो बजट से पहले आप ऐसा करते हैं और उसके बाद बजट में आप टैक्स लगाते हैं और फिर सप्लीमेंटरी बजट लाते हैं। इस तरह से बार बार जो बजट आप लाते हैं, उससे चीजों के दाम बढ़ते हैं और एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से भी चीजों के दाम बढ़ाते हैं।

एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि प्रोडक्टिविटी आप की घट गई है। अभी छठी पंचवर्षीय योजना का एप्रेजल आया है और इसलिए सबको पता है कि कितना टार्गेट एचीव किया गया है। जो प्लान का आउटले आपने रखा था, उससे 15 से 20 परसेन्ट आपने कम कर दिया है क्योंकि

जो आपने टार्गेट रखा था, उतना पूरा नहीं हो सकता है। कोल का टार्गेट 165 मिलियन टन रखा था और अब उसको 154 मिलियन टन कर दिया है और यह भी लक्ष्य जो आपने रखा है, इसका 50 परसेन्ट भी अगर आप पूरा कर लेंगे, तो मैं समझती हूं कि कुछ समाधान हो जाएगा। इसी तरह से रेलवे के बारे में आपने 309 मिलियन टन रखा था लेकिन अब वह फीगर घटकर 290 से 285 मिलियन टन तक आ गई है। फूड प्रोडक्शन के बारे में आप कह रहे थे कि रिकार्ड प्रोडक्शन हम करेंगे। आपको पता है कि 1978-79 में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन हुआ था और इस साल का जो टार्गेट आपने रखा था, वह टार्गेट भी पूरा नहीं कर सके हैं। आपने फाइव इयर प्लान में 154 मिलियन टन का टार्गेट रखा था लेकिन उस टार्गेट को कम करके आपने 146 से 148 मिलियन टन कर दिया है और पावर जेनरेशन भी 30 परसेन्ट आपका कम हो रहा है और पावर की शार्टेज की वजह से इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन और दूसरी चीजों के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ रहा है। सब जगहों पर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। जहां पर डेफीसिट फाइनेंसिंग चलती है, तो उसके साथ अगर प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा और आप अपने टार्गेट पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है कि प्राइस स्टेबीलिटी लाने में आप कामयाब हो सकते हैं।

लेकिन आपका कहना यह है कि प्रोडक्शन हो रहा है। मिस्टर तिवारी इन्डस्ट्री मिनिस्टर ने कहा कि पिछले तीन सालों में 4-5 परसेन्ट प्रोडक्शन बढ़ा जबकि हमारा टारगेट 8 परसेन्ट प्रोडक्शन बढ़ाने का था। अगर आपको अपना टारगेट पूरा करना है तो आने वाले दो सालों में आपको 12 परसेंट प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसके बारे में फिक्की के मिस्टर जैन ने यह कहा है कि हम ये टारगेट जरूर अचीव कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमारे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे यहां कोल का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से मिलनी चाहिए। अगर आप उनकी ये सारी चीजें सुलभ करा दें और जो कंसेशंस वे मांगते हैं वे दे दें तो आपके टारगेट्स पूरे हो सकते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि आपके ये टारगेट्स पूरे नहीं हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप मनी सप्लाई पर कंन्ट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कम नहीं कर रहे हैं। आपके हर बजट में डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ती गई है, बेशक आप आंकड़े कुछ भी बताइये। इससे प्राइसिज भी बढ़ती गई हैं।

मेरी आप से प्रार्थना है कि आपको ब्लेक मनी को कर्टेल करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। वांचु कमीशन ने कहा है कि देश में कितनी ब्लेक मनी है इसका अन्दाजा नहीं लग सकता है। अभी नहीं तो दो साल बाद आपको पता चलेगा कि आज देश में व्हाइट मनी से ब्लेक मनी बहुत ज्यादा है। वांचु कमीशन ने कहा है कि हमें अपना टेक्स स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। टेक्स स्ट्रक्चर को सिम्पलीफाई करना पड़ेगा। हमें डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। आपने 1946 में यह किया था जो कि सफल नहीं हुआ। उसके बाद आपने वियरर कोण्ड्स दिये है। उनसे भी आपको एक हजार करोड़ रुपया ही मिल पाया होगा। मुझे लगता है कि आप नान रेजीडेंट इन्डियंस से यहां जो इनवेस्टमेंट करा रहे हैं, वह भी यहां से ब्लेक मनी को भेजकर फिर उसे व्हाइट मनी के रूप में मंगाना है। मेरा मत है कि आपको हंड्रेड रुपीज के नोट्स का डिमोनेटाइजशन करना चाहिए। यह ब्लेक मनी सौ रुपये के बंडल्स में चलती है। अगर आप सौ रुपये के नोट का डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं तो आपको ब्लेक मनी करटेल करने में बहुत सफलता मिलेगी। यह ठीक ही है कि इससे भी सारी ब्लेक मनी करटेल नहीं हो सकती है। आपको पेकेज डील के रूप में दूसरे कदम भी उठाने पड़ेंगे।

मेरी आप से प्रार्थना है कि आपका पब्लिक डिस्ट्रियब्युशन सिस्टम टोटल्ली कलेप्स कर गया है। दिल्ली शहर तक में दुकानों में चीजें नहीं

मिलती हैं। गांवों की बात तो अलग रही। आपने इन दुकानों पर मिलने वाली चीजों के दाम भी बढ़ा दिए हैं। आपने आई० एम० एफ० से लोन ले कर इन चीजों पर सब्सीडी कम कर दी है।

हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होनी चाहिए। हमारे देश में प्राइस फिक्सेशन कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी में प्रोडयुसर भी रहें और कंज्युमर भी रहें। आप प्रोड्युसर और कंज्युमर के बीच में कम से कम मिडिल मेन को रखिये।

आपको ऐसी विजिलेंस कमेटी नियुक्त करनी चाहिए जो कि प्रोक्योरमेंट लेवल से लेकर डिस्ट्रियव्युशन लेवल तक विजिलेंस का काम करें। वह सारी जगहों पर निगरानी रखे और देखें कि कहीं ब्लेक मार्किटिंग या होडिंग तो नहीं हो रहा है।

एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूं आर्टिफिशियल स्केअरसिटी के बारे में। हमारे वनस्पति डायरेक्टेरेट ने 81-82 में एक आर्डर निकाला कि 90 परसेंट प्रोडक्शन स्माल पेकेट्स में सप्लाई की जानी चाहिए। इससे मार्केट में वनस्पति की अवेलेब्लिटी कम हो गई। आज ही हम डिसकस कर रहे थे और पांडे जी बहुत गुस्सा हो रहे थे बीफ टैलो की बात को लेकर। छः महीने बाद जाकर मिनिस्टर ने मानी जब मैंने प्रूफ दिया कि वनस्पति में बीफ टेलो डाला जा रहा है। 25 जुलाई का इनका जवाब है कि यह सही नहीं है। इन्होंने कहा था :

"It is impossible to adulterate vanaspati with beef tallow."

उसके बाद भटिंडा वाली बात होने के बाद इस सदन में आपने मंजूर किया इस बात को।

Please withdraw this order.

अगर आप आर्डर को विदड्रा नहीं करेंगे तो जब चालीस परसेंट डिमांड बढ़ जाती है और आप दस परसेंट सप्लाई कम कर देते हैं तो उसका नतीजा यही हो सकता है कि देश में उस वस्तु की आर्टिफिशल स्केरसिटी जैसे ट्रेडर्ज पैदा करते हैं वैसे ही सरकार भी कर देती है और कंज्यूमर्ज को ब्लेक में, बढ़ी हुई कीमतों पर और एडल्ट्रेटिड लूज वनस्पति खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी कोई तरकीब आप करें, ऐसे कोई कदम आप उठाएं ताकि कंज्यूमर्ज को ब्लैक में लूज खरीदने के लिए मजबूर न होना पड़े।

मैं कुछ सुझाव देकर समाप्त कर दूंगी :

1. Stricter control over money supply ;
2. Prevent huge deficit financing ;
3. Take measures like demonetisation ;
4. Unearthing of black money ;
5. Refusal to have Bearer Bonds and put premium on black money ;
6. Strict monitoring to ensure that unaccounted money is mopped up by licence scandals ;

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your suggestion that there should not be currency notes but only coins is a very good suggestion.

श्रीमती प्रमिला वंडवते : ऐसा आप कुछ न कीजिए जिससे आनेस्ट पनिश होता हो। ऐसा करके जो लोग तनख्वाह लेते हैं उनको आप सजा देते हैं। ब्लेक मनी को इनवैस्ट करने का जो प्रावधान आप करते हैं, उस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं कंज्यूमर मूवमेंट में काम करती हूं। अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट्स होती हैं। इसलिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास हमें जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री का निर्माण किया जाना चाहिये। उस मिनिस्ट्री के पास जाकर हम अपने सारे सवाल हल करवा सकते हैं।

प्राइस फिक्सेशन बोर्ड आप रखे जिसमें कंज्यूमर्ज के प्रतिनिधि, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि और प्रोडयूसर्स के प्रतिनिधि रहें। विजिलेंस कमेटीज

राइट फ्राम दी प्रोक्योरमेंट टू दी डिस्ट्रीब्यूशन लेवेल अलग अलग स्तरों पर होनी चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी आपको स्ट्रैंगथन करना चाहिए। यह सब आप करेंगे तो मैं समझती हूं कि शायद प्राइस राइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप ईमानदारी से इसको करेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं और इससे कोई इन्कार भी नहीं कर सकता है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जिनके परिवार बड़े हैं उन्हें इस मंहगाई से सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन प्रमिला जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि इस महंगाई से आम जनता पर या गांव में जो लोग हैं उन पर हमारी सरकार चोट करना चाहती है और ज्यादा चोट कर रही है। सरकार तो मंहगाई को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जहां तक सम्भव हो सकता है वह सुदृढ़ कर रही है और इस दिशा में वह प्रयत्नशील, काफी प्रयत्नशील है ताकि गांवों में आम जनता का जो आवश्यक सामान है, जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उपलब्ध हो सकें। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कहीं त्रुटि रह जाती है जिसके लिए पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक कमेटियां बनी हुई हैं जिनका यह काम है कि वे देखें कि मूल्यों को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए, वहां कहीं न कहीं कुछ ऐसी त्रुटि रह जाती है जिसके कारण महंगाई पर सही रूप से काबू पाना सम्भव नहीं हो सकता है।

थोक मूल्यों का सूचकांक जरूर बढ़ा है। मार्च 1983 में वह 294.3 था और अप्रैल में वह 297 हो गया।

और मई में 304.6 तथा जून में 307.1 था। महंगाई जो बढ़ती चली गई इसके अनेक कारण हैं, मुद्रा प्रसार भी एक कारण है। काले धन की दिनों-दिन जो बढ़ोत्तरी हो रही है वह भी एक कारण है। गेहूं पिछले साल 2.20 प्रति किलो था वह इस साल 3.50 हो गया, चावल 3.25 से बढ़कर 4 24 हो गया। और जो अन्य वस्तुएं हैं उनके बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि जब औरतें घर ग्रहस्थी का सामान लेने जाती हैं तो उनको बहुत अखरता है। महंगाई को लेकर परिवार में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है जब शाम को लोगों को कभी दाल मिलती है तो रोटी नहीं मिलती, और रोटी मिलती है तो दाल नहीं मिलती। लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। हमारा देश गरीब है रोज उपयोग में आने वाली चीजें खरीद नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयत्नशील नहीं है। सरकार प्रयत्नशील है, पर प्राकृतिक प्रकोप का हम क्या कर सकते हैं? कभी सूखा तो कभी बाढ़ जिनके कारण करोड़ों रु० का खर्च हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी जो सुरसा की तरह हमेशा मुंह बाये हुए है। अगर इसको नहीं रोका तो मूल्य वृद्धि रोकना मुश्किल होगा।

जो विदेशों से भारी कीमत पर सामान आयात होता है उससे भी मूल्य वृद्धि होती है। इसलिए आयात की तादाद को कम करना चाहिए। लेकिन यह मतलब नहीं है कि सरकार मूल्य पर नियंत्रण नहीं रखे। सरकार का दायित्व है कैसे मूल्य पर नियंत्रण किया जाए। सरकार ने जो अभी लिक्विडिटी रेशियो को घटाया है वह सराहनीय है। जब भी मुद्रा का प्रसार होता है और मांग अधिक होती है तो महंगाई होती है और राज्य सरकारें घाटे का बजट प्रस्तुत करती हैं जिससे हमें महंगाई का प्रकोप भाजन बनना पड़ता है। और योजना में भी बड़े साधनों की जरूरत होती है, उसके लिए भी हमें खर्च करना पड़ता है जिससे महगाई बढ़ती है।

प्रधान मंत्री हमेशा कहती रहती हैं और जो 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ी हुई योजनायें हैं उनमें प्रसार की धीमी प्रगति होती है तो उसके लिए चिन्ता प्रकट करती हैं क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए एक माध्यम है और जो मूल्यों को भी नियंत्रण में रख सकता है क्योंकि यह कार्यक्रम ग्रामीण वर्ग के कमजोर लोगों के लिए ही है

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इन योजनाओं के कार्यान्वयन का काम राज्य सरकारों को सौंपा गया है। लेकिन इसके लिए हमें समन्वय स्थापित करना चाहिए और देखना चाहिये कि किस तरह से मूल्य नियंत्रित करके आप जनता को राहत पहुंचा सकते हैं।

लेकिन यह मैं जरूर कहती हूं कि आम आदमी की जो क्रय शक्ति है उसको देखते हुए जो आर्थिक रियायतें दी जा सकती हैं वह देनी चाहिएं और मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाने के लिए जो जिन्दगी की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कठिनाइयों के बावजूद प्रशंसनीय काम कर रही है।

इस बारे में दो मत नहीं हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि वित्त मंत्री सदन को बताएं कि वह महंगाई को काबू में करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Finance Minister in his statement pretends to exude confidence, but at the end of his statement, in the last paragraph of his statement, he cautions us against complacency and hints that every possible step should be taken against inflationary trends. In his statement he has tried his very best to juggle with the figures and present before the country a position as if it has really been possible for the Government to contain inflation and contain spiralling of prices. In attempting to do so, very selectively and carefully he has taken a time span in order to arrive at certain conclusions which will substantiate his arguments. For example, he says :

> "In the 11-week period from 14th May to 30th July, 1983, wholesale prices increased by 2.5 per cent which is significantly lower than the increase of 5.4 per cent during the same period in 1982-83..." etc., etc.

I do not see what is the justification for his picking up the date of 14th May, why he should start his exercise of assessing the price rise from 14th May. 1st April is the beginning of every financal year. 28th February is the presentation of the Budget. The figures of 26th February are available. I could have understood if he had taken 26th February ; I could also have understood if he had taken 1st April, the beginning of the financial year. But, instead, he has taken 14th May, because that is the most convenient time for him. If he takes the time span between 14th May and 30th July, it suits his purposes. Now I will give you the figures. If you take, instead of a 11-week period, a 23-week period beginning from the 26th February 1983, because on 28th February you placed your Budget, to 6th August, 1983—that is the latest figure ; when you made the statement, it was not available, but now it is available—the rate of inflation comes to 7.12 per cent, not your 2.5 per cent. If you take 1983 alone, from January 1983 to the week ending the 6th August, 1983, then the price increase per month comes to 4.01 per cent, not 2.5 per cent.

Mr. Deputy-Speaker, he has taken all these figures and made all calculations to arrive at certain conclusions. Actually he had arrived at the conclusion first and then he tried to fix up the premises, he went backwards ; it is a sort of inverted logic that he has propounded in his statement.

Because the time is very short, I will go over from the wholesale price index to the consumer price index. What is the situation in consumer price index ? As Mrs. Pramila Dandavate was saying, actually the market prices as reflected in the consumer price index are not reflected in the wholesale price index.

Day before yesterday, I myself went to Karol Bagh and purchased one kg. of potato. It cost me Rs. 2.00. Yesterday the same quantity of potato cost me Rs. 3/. This is a fact.

PROF. MADHU DANDAVATE : This is excluding the transport charge.

SHRI SUNIL MAITRA : That is right.

So far as the consumer price index is concerned, I have got with me the statistics for a ten year period prepared by your Labour Bureau—Labour Bureau of the Government of India. It has been published in the Indian Labour Journal. If you really study the trend of prices in the consumer price index, the situation that arises, the picture that arises, is really something very fearful. It is not that I am here just to spite the Government or to abuse it or to vilify the Government. I am not saying this for the sake of criticism. There is this dangerous trend that is appearing. In 1983, if you take three months, somewhere in his statement, he has stated that due to seasonal variation, there is some price rise. If you compare it backwards, then I say that your seasonal variation argument will not stand, excepting marginally. In the month of April, the Consumer Price Index was 508 with 1960 as the base year. Then, in the month of May, it shot up to 521—a 13 point rise in one month in the all-India Average Index. It has never happened in the past except in 1974. Please check up my statement. I have been studying this and so I have been telling you that there was a 13 point rise in one month.

You will find that only in 1974, between August-September, the rise was of 13 points—from 321 it rose to 334 points. And, in between 1974 and 1983, in all these years, you will find that in one month there was an increase registering a 13 point rise. What happened in the month from May to June ? As against 521 registered, the rise was of 12 points. It shot up to 533 points. What was the trend in 1974 ? This was the trend in 1974 and your Government could not control it. In June 1975, there was the emergency. In any society, economy is the foundation and on it is built the political and social superstructure. The superstructure shows signs of cracks when the foundation starts subsiding. This was what happened in 1975 which led to emergency and the rape of democracy. Similar situation we are approaching because of the rising prices in the year 1983 (*Interruptions*) I am not holding any brief for the Janata Government. So far as economic issues are concerned, we find no difference between the Congress Party Government and the Janata Government. But it should be to their credit all through the prices were more stable in the year 1977-78. Mr. Dev, this has been published in your journal. You did not study it. How can I help an ignorant man. Please read it and study it, Mr. Dev. (*Interruptions*) What are the reasons for the unchecked price spiral ? What is the reason for this—firstly it was due to a continuous increase in the indirect taxes. In 1950, we used to pay Rs. 62 crores by way of excise duty and in this year's budget it is more than Rs. 9,000 crores. What is the excise duty, Mr. Minister ? In the morning when I get up and take a cup of tea, for tea leaves I pay excise duty and for sugar I pay excise duty. When I smoke a cigarette I pay excise duty on it and also excise duty on the match stick. For medicines I pay excise duty and when I die and my body is wrapped up in a piece of new cloth then I pay excise duty for the new cloth. This is the excise duty and the result is price rise.

Next is inflation. One of the biggest sources of inflation is deficit financing. Leave aside your budgetary deficit. What about your supplementary budget. I happen to be the Chairman of a parliamentary committee. It so happens that I have been the member of this parliamentary committee for the last three years. Now, I am realising the impact of your budgetary exercises to my utter dismay. During my college days it was not taught to me that a budget can be dragged on for 3-4 years. Then with how many suplementary budgets you come and after 2-3 years you persuade this House to sanction excess expenditure. Therefore, your usual figures of deficit are not the real figures. The figure goes on increasing and nobody has calculated what is the actual amount of deficit in a particular year. That may be ascertained after 4-5 years. The more the inflation the more the price rise.

Thirdly, you allow the monopoly capitalists to go on minting more and more profit because in order to develop capitalism in the country you want to accumulate capital and the principle of elementary economics is that the more the profit the more the capital. Sir, when the Britishers left this country the total assets of the Tatas and Birlas were Rs. 60 crores and today it is

more than Rs. 3,000 crores. It is as a consequence of the planned policy of the Government of India which they have been following for the last 36 years. The result is that monopolists have amassed wealth by jacking up prices and your policies are squarely responsible for this price rise.

Sir, the Finance Minister in his statement has stated that some measures have been taken to mop up excess liquidity. What is the reason for this excess liquidity in the economy he has not stated. Apart from other reasons, yesterday when I was listening to your submission in the Swraj Paul debate you stated in your reply that every month more than Rs. 100 crores are coming to this country. If every month Rs. 100 crores are coming to you then are Rs. 100 crores being matched by equal amount of goods and services ? If it is not so, then there is bound to be excess liquidity and what are you going to do about the excess liquidity ? This quack way of trying to hold the price line will not succeed as it has not succeeded earlier.

I am not going into the impact of external borrowing on the price situation in the country ? It has got a very great adverse impact. If today it is not felt, I am sure, by 1985-86 and 1986-87 the impact of your external borrowing will be felt by the economy as a whole, in the form of tremendous rise in prices. You should not go in for these borrowings. So, what is to be done ? Have you developed the public distribution system as you promised ? No. You have not done it. What is the condition of the public distribution system today ? Mrs. Dandavate stated that in the public distribution system nothing is available. Even your your existing public distribution system is being dismantled. I would like to refer to Unstarred Question No. 772 dated 16th July 1982. The question asked was : "How many fair price shops were increased in the country during the last three years ?" Your answer says this : "1980, 2.75 lakhs ; 1981, 2.97 lakhs, 1982, 2.84 lakhs." This is from your answer. I am quoting it. Is this the way of expanding your public distribution system ? You assured us that you would take this seriously ; you have not done it, your Government has not taken it seriously. I suggest to you to take the following immediate steps :

Number one : You should strengthen your public distribution system.

Number two : You should resort to nationalisation of wholesale trade in foodgrains. You will have to do it ; there is no escape from it. That is the only way.

Number three : You should procure at least 14 essential commodities of daily life like rice, wheat, pulses, soap, edible oil and so on,—you should procure it centrally and supply them to the States and fix their prices within the purchasing power of the people ; you must distribute them through fair price shops. The hon Minister, I know, while replying to my points,—if he cares to refer to them, would say, where is the money needed for such a huge subsidy, I would just like to draw your attention to the ASIAD jamboree which took place in Delhi. At that time you decided to construct a Ring Railway around the city of Delhi ; it cost you Rs. 33.41 crores. The projection by the Housing Minister, Shri Buta Singh—he is coming in now—was this. The projection was that 2.80 lakhs people would travel by this Ring Railway. But what is the position now ? The hon. Railway Minister gave me reply in writing. In reply to my unstarred question, he says that only 209 persons have been using the Ring Railway daily today. This is the present position. Instead of the projection of 2.80 lakhs people, the present number of people who travel is only 209. You have spent already more than one thousand crore. You cannot plead you have no money. You have money. You have squandered public money unnecessarily. If you have a sense of responsibility and obligation to the people to whom you pledged at the time of the election, then one of your main and important measures is to hold the price line. Please do have some sympathy for the common people, for the weaker sections and please accept the suggestions which I have made.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे पक्ष और विपक्ष के मित्रों ने जो बात यहां पर कही, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो स्टेटमेंट 18 अगस्त को इस सदन

में दिया गया था, उस में जो चिन्ता माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर व्यक्त की थी, उसी के अनुरूप उनकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं और किसी को भी इससे इंकार नहीं हो सकता कि कीमतों के बढ़ने से भारत जैसे मुल्क में, जहां बहुत सारा प्रतिशत गरीब लोगों का है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन के ऊपर, जिनके जीवनयापन पर साधारण मूल्य वृद्धि का असर पड़ता है और निश्चित तौर पर कीमतों में कुछ भी वृद्धि होना हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि सरकार भी इसके लिए समान रूप से चिन्तित है मगर सवाल यह पैदा होता है कि इस स्थिति का मुकाबला कैसे किया जाए। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सारे सदन का आवाहन किया है और इस सदन के माध्यम से सारे देश का आवाहन किया है। अकेले कानून के जरिये से, अकेले सरकार द्वारा कुछ सख्त कदम उठाने से मूल्य वृद्धि नहीं रुक सकती। हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं और इस सदन में भी ऐसे मेजर्स लाई है और उन को सख्ती से पालन करवाने की चेष्टा भी हुई है लेकिन कुछ सरकारों ने उन को नहीं माना है। मार्कसिस्टों ने, जिनकी सरकार पश्चिम बंगाल में है, जब हमारी सरकार ने जमाखोरों के विरुद्ध कानून बनाया और ब्लैक-मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ जब कानून बनाया, तो अपने राज्य में उन कानूनों को लागू करने से इन्कार कर दिया। यह उनकी ईमानदारी का सुबूत है मगर मान्यवर मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग मिलजुल कर सरकार की मदद करे और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, उसमें उस की मदद की जाए, उसकी सहायता की जाए। आज जबकि हमारा नारा यह है कि उत्पादन बढ़ाओ, तो हमारे विपक्ष के मित्र यह कहते हैं कि हड़ताल करो और यह एक साधारण सी बात है कि यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, यदि कारखाने नहीं चलेंगे, तो मूल्य वृद्धि कैसे रुकेगी। ये लोग हड़ताल करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और यह एक अलग बात है कि ये जिन लोगों को हड़ताल करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों का इन पर कितना विश्वास है और कितनी वे इनकी बात मानते हैं। हम कहते हैं कि रेलें चलें और यह कहते हैं कि रेलें रुकें। हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करो और देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे आओ, तो ये भारत बंद का नारा देते हैं। इस तरह का निगेटिव एटीट्यूड यदि विपक्ष का रहेगा, विपक्ष के हमारे मित्रों का रहेगा, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है, वे अगर रुकेंगे नहीं तो कम से कम उनकी गति मन्द तो पड़ ही सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि जैसे प्रश्न को वे अकेले सरकार का काम न समझें, उस को सारे राष्ट्र का काम समझकर अपना भी समान रूप से दायित्व समझें और सरकार जो कदम उठाए, उसमें उनको उसकी मदद करनी चाहिए।

मान्यवर, मूल्य वृद्धि के लिए विपक्ष के लोग सरकार की अवहेलना करते है, सरकार को दोष देने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हमने कड़े से कड़े कदम उठाए हैं और उनका बहुत कुछ असर भी हुआ था। सन् 1975 और 1976 में सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण पाने में सफलता पाई थी मगर 1977 के बाद जो सरकार यहां पर बनी, जो मित्र यहां पर बैठे हैं, उनमें से कई लोग उस सरकार की मंत्री-परिषद में भागीदार भी रहे हैं।

इन लोगों ने जो इकोनोमी देश में चलाई वही सबसे बड़ा कारण है कि हम मूल्यों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर पाये हैं। इसके लिए वे बहुत बड़े दोषी हैं। कोई भी भारतवासी 1977 को नहीं भूल सकता है और 1979 का वर्ष तो वह वर्ष था जब हमारे श्री रशीद मसूद के मसीहा चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री थे और उस वर्ष देश में इन्फलेशन 27 प्रतिशत था जो कि सबसे हाई इन्फलेशन था। चीजों के दाम आसमान को

छू रहे थे और इसकी कोई इन्तिहा नहीं थी।

1980 में शासन में आने के बाद हमने एक के बाद एक अच्छे कदम उठाये। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में चीना का उत्पादन कम हो गया था जिसके कारण हमें चीनी आयात करनी पड़ी। उसके बाद गेहूं की कीमतें बढ़ने की संभावना थी जिसके लिए हमें गेहूं का आयात करना पड़ा। हमने यह आयात इसलिए किया जिससे कि स्वदेशी बाजार को नियंत्रित किया जा सके। हम अब जब चावल मंगा रहे हैं तो उससे भी हमारे विरोधी पक्ष के लोग पोलिटिकल केपिटल बनाने की सोच रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मित्रों ने इस तरह के कदमों को उठाया, विपक्ष के मित्रों ने जिससे न वे देश का लाभ कर रहे हैं और न अपना ही लाभ कर रहे हैं।

जिस तरीके से हमारे विरोध पक्ष के मित्र सरकार के साथ नान-कोआप्रेशन के रास्ते पर चल रहे हैं उसी का परिणाम है कि जितने भी चुनाव देश में हुए, उनमें कांग्रेस के लोग जीत कर आये। किसी भी लेवल के चुनाव हुए हों, सभी में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। कम्युनिस्टों के गढ़ों में, लोक दल के गढ़ों में कांग्रेस की जीत हुई है। विपक्ष के लोग बोल सकते हैं, हल्ला-गुल्ला मचा सकते हैं लेकिन जहां ठोस काम करने की जरूरत पड़ती है, उसको वे नहीं कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि विपक्ष किस प्रकार से प्ले करता है, हमें इसको नहीं देखना है, हमें अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग और सचेष्ट रहना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कीमतों को न बढ़ने दें। आपने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि असेंशल आइटम्स की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं जिससे आम आदमी का जीवन कष्टप्रद होता जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जैसा कि हमारे मित्र श्री सुनील मैत्रा साहब ने भी कहा है कि आपको कुछ आइटम्स को जो कि आपको असेंशल लगें, उनको सरकार को प्रोक्योर कर के अपने पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम से बंटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप असेंशल आइटम्स सब्जी है, तेल है, प्याज है या दूसरी चीजे हैं इनकी कीमतों को आप नहीं रोक पायेंगे। मेरा आप से आग्रह है कि जहां आपको पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए, वहां पर उसको अधिक एरिये तक पहुंचना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये असेंशल आइटम्स सस्ती दरों और समान दरों पर सभी को मिल सकें।

मान्यवर, कीमतें बढ़ने की बात इस सदन में उठती रही है और आज भी उसी पर चर्चा चल रही है। इस विषय में प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक एपेक्स बाडी होनी चाहिए और उसके बोर्ड हों जो कि डिस्ट्रीक्ट लेवल से ताल्लुका लेवल तक हों। जैसा कि एक राष्ट्रीय उपभोक्ता समिति बनाने की बात उठी, वह ठीक बात है। प्रमिला जी ने सभी स्तरों पर विजिलेंस कमेटी बनाने की बात भी कही, वह भी होनी चाहिए। जब तक हम प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्ट्रिब्युशन लेवल तक पर विजिलेंस नहीं रखेंगे, सजग नहीं रहेंगे तो हमेशा लोग बीच में उसमें घपला पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसके माध्यम से कोई एपेक्स बाडी बनायी जा सके और उसके माध्यम से उपभोक्ता आन्दोलन को भी चलाया जा सके। समय-समय पर मूल्यों का निर्धारण करने के लिए भी कोई बाडी बननी चाहिए।

18 hrs.

अन्त में मेरा अपने विरोधी मित्रों से निवेदन है कि इस मामले में, इस प्रकार के कार्यों में उनको सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये। उनको देखना चाहिये कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। हमारे चारों तरफ जितने राष्ट्र हैं उनमें भी कीमतें बढ़ी है और ऐसे देशों मे बढ़ी हैं जहां डैमोक्रेटिक सेट अप नहीं है, प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं है। हमारे यहां डैमोक्रेटिक सैट अप है। विभिन्न प्रकार के पुल्ज एंड प्रैशर्ज में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनके लिए वित्त मंत्री जी तथा

प्रधान मंत्री जी बधाई की पात्र हैं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मुहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब। जो आदमी सो रहा हो उसको तो जगाने की कोशिश की जा सकती है और किसी नतीजे की तवक्कह की जा सकती है लेकिन जो आदमी जाग कर भी सो रहा है, उसको जगाने से कोई फायदा नहीं है। सरकार जाग रही है साहब ये लोग इम्प्रैशन दे रहे हैं कि सो रही है। हम इसको कैसे जगा सकते हैं, यह हमारे बस की बात नहीं है।

1980 में कांग्रेस आई की सरकार ने, मुहतरिमा प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने और मुख्तलिफ बुजरा साहिबान ने कहा था कि हम सिर्फ प्याज की कीमत पर जीत कर आए हैं और सेंटर में सरकार बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि एक बार से ज्यादा बार यह कहा था कि हमारा फर्ज यह होगा कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करें और कंट्रोल ही न करें बल्कि उनको नीचे लाने की कोशिश भी करें। श्री हरीश रावत की तकरीर सुनकर मुझे ताज्जुब से ज्यादा अफसोस हुआ।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : अकेले सोने की बात है। बी० जे० पी० के साथ सोयेंगे तो मुश्किल हो जाएगी जागना।

श्री रशीद मसूद : बी० जे० पी० वाले तो सोते ही नहीं हैं। हमें भी जगा कर रखेंगे ये। 1980 में आपने सरकार सम्भाली। उस वक्त के मिनिस्टर साहब ने बड़े जोरदार अलफाज में हाउस में कहा था कि हमारा मकसद न सिर्फ यह होगा कि कीमतों को बढ़ने से रोकें बल्कि कीमतों को नीचे हम लाएंगे। इन बढ़ती हुई कीमतों की जिम्मेदारी आपने जनता और लोक दल की सरकार पर डाली थी। हरीश रावत साहब कह रहे थे जो कि इनसे पहले जो मिनिस्टर थे वह भी कहते थे और उनको हटा दिया गया था और दूसरे मिनिस्टर को लाकर इनचार्ज बना दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस बात को तसलीम किया था कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

डाटा आपने नहीं देखा है इसलिए आपको इल्म नहीं है। जनता और लोक दल की सरकार की बात आप कर रहे हैं। मैं कंज्यूमर इंडैक्स की बात करता हूं। जनता सरकार 2 साल 5 महीने हकूमत में रही। मार्च 1977 में यह इंडैक्स 312 था और जुलाई 1979 में जब जनता सरकार यहां से हटी तो 350 था। जुलाई से दिसम्बर 1979 तक पांच महीने लोक दल की सरकार रही। इन पांच महीने में 359 प्लाइंट्स से लेकर उसने 371 प्लाइंट्स पर इसको छोड़ा। पूरे पांच महीने में बारह प्वाइंटस का ही इजाफा हुआ। अगर इसको आप पूरे महीने के लिहाज से देखेंगे तो जनता सरकार के 2 साल 5 महीनों में हर महीने औसत कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स 8.81 बढ़ा और लोक दल की सरकार के पांच महीनों में 17 फरवरी 1971 को यहां फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 1971 में ऐसा सूखा पड़ा जो उससे पहले कभी नहीं पड़ा था और उसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ था, उसको देखते हुए इन पांच महीनों में तीन प्वाइंट्स की हर महीने इसमें इजाफा हुआ।

और गवर्नमेंट दैट वर्क्स के चार साल के दौरान इन्होंने जब सरकार सम्हाली थी तो उस वक्त कन्जूमर्स प्राइस इंडेक्स था 371 और आज वह बढ़कर 543 हो गया है। मतलब यह कि हर महीने 5.31 पौइंट का इजाफा हुआ है कंज्यूयर्स प्राइस इण्डेक्स में। हरीश रावत जी बार बार कह रहे थे कि जनता सरकार और लोक दल सरकार के जमाने में क्या था? तो आप खुद देख लीजिये कि हमारे जमाने में और आपकी सरकार के जमाने में कितना इजाफा हुआ है।

यही नहीं 1981 की तकरीर में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि होलसैल प्राइस इण्डैक्स अपनी जगह पर रुक गया है। लेकिन क्या कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स रुका जिससे आम आदमी का ताल्लुक है? उन्होंने यह भी कहा था कि अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गये हैं जब जल्दी कीमतें गिरनी शुरू हो जायेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बराबर इजाफा हो रहा है। आप अपोजीशन

से किस किस्म की मदद चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी करें हम आंख मींचकर आपकी तारीफ करते चले जायें तो यह नामुमकिन है। हमारा तो फर्ज ही है कि सरकार की गलतियां बतायें, लोगों की तकलीफें आपके सामने रखें। आपने चार साल में कोई तारीफ का काम ही नहीं किया। कीमतें बढ़ी, इंस्टीट्यूशन्स बरबाद किये, ला ऐंड आर्डर तबाह कर दिया, क्या इन सब की हम तारीफ करें? एक साहब कह रहे थे कि जनता सरकार के जमाने में शाम को 4 बजे के बाद दिल्ली में औरतें निकलते डरती थीं। लेकिन कांग्रेस सरकार के जमाने में 5 बजे के बाद दिल्ली शहर में आदमी निकलते डरते हैं। क्या इसके लिये आपकी तारीफ करें।...(व्यवधान)

आप ठंडे दिल से गौर करें। अगर यह बात आप कहने लगें कि हर चीज आसानी से मिल रही है, कोई कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ गया, दो साहब में लड़ाई हो रही थी, एक साहब कह रहे थे कि कीमतें बढ़ रही हैं, और दूसरे साहब कह रहे थे कि नहीं बढ़ रही हैं। जो साहब कह रहे थे कि कीमतें नहीं बढ़ रही हैं उन्होंने कहा मैं जब बाजार जाता हूं तो सब चीज मिल रही है, दूसरे साहब कह रहे थे कि मुझे तो मिलती ही नहीं हैं, जब घर जाता हूं तो परेशानी ही सामने नजर आती है। तो जो साहब कह रहे थे कि कीमतें नहीं बढ़ रही हैं उन्होंने कहा कि अगर आपको चीजें नहीं मिलती तो यह आपकी बेवकूफी है क्योंकि आप जाते होंगे सदर बाजार या चांदनी चौक। अगर आपको खरीदना है तो टी० वी० और रेडियो से खरीदिये।

आपकी कीमतें बढ़ने की सबसे पहली वजह यह है कि हमारा किसान जो चीजें पैदा करता है, उन में जो इनपुट्स वह इस्तेमाल करता है उनकी कीमतें आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से किसानों को बिलकुल मुनाफा नहीं हो रहा है। आप देखिये फर्टिलाइजर में आपने क्या कर दिया है—60 परसेन्ट से ज्यादा बढ़ा दिया है...

एक माननीय सदस्य : उसमें तो कम हुआ है।

श्री रशीद मसूद : कम करने का क्या तरीका है—पहले 100 परसेन्ट बढ़ा दिया और उसके बाद 25 परसेन्ट घटाकर आप यह कहें कि हमने 25 परसेन्ट घटा दिया है—इसे घटाना नहीं कहा जा सकता। इनपुट्स की कीमतें इतनी घटाइये जिस से हर चीज किसान को मार्केट में सस्ती मिले, जैसा जनता पार्टी के दौर में होता था।

श्री हरीश रावत : खुदा से डरिये, इतना बड़ा** न बोलिए।

श्री रशीद मसूद : क्या मैंने गलत कहा है? आपने इनपुट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं, पानी की कीमतें बढ़ाई हैं, बिजली की कीमत बढ़ाई है, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाई है, लगान आपने बढ़ाया है—इन सबका नतीजा है कि किसान जितनी चीजें पैदा करता है अल्टीमेटली उनकी कीमतें बढ़ेंगी, जबकि उनमें किसान को कोई प्रोफिट नहीं हो रहा है। किसान जो इनपुट्स इस्तेमाल करता है उनकी कीमतें कम कीजिए ताकी उसको सस्ती मिल सकें और उसको फायदा हो सके। आज न किसान को फायदा हो रहा है और न कन्ज्यूमर को फायदा हो रहा है। सारे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है।

प्रमिला जी ने कहा था कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह कम्पलीटली फेल हो गया है...

श्री हरीश रावत : कम्पलीटली?

श्री रशीद मसूद : मुकम्मिल तौर पर।

श्री हरीश रावत : इसको कम कीजिए।

श्री रशीद मसूद : थोड़ा सा कम कर दो। रावत जी मेरे दोस्त हैं—95 परसेन्ट फेल हो गया है। आपकी ये शाप्स लोगों को सही चीजें नहीं देती

**Expunged as ordered by the Chair.

हैं, बल्कि एडल्ट्रेटेड चीजें आपके सुपर-बाजार में मिल रही हैं। इस पर कौन कंट्रोल करेगा? इसमें अपोजीशन से किस किस्म की मदद चाहते हैं— बतलाइये?

करप्शन क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि मुलाजिम-पेशा लोग हैं, जिनकी फिक्स्ड सेलरी है, उनकी बीबी 30 दिन का अपना बजट बनाती है, लेकिन 15 दिन गुजरते-गुजरते कीमतों में 50-60 परसेन्ट का इजाफा हो जाता है, नतीजा यह होता है कि उनका बजट फेल हो जाता है, बाकी के 15 दिन वे कहां से खायेंगे? लिहाजा वह नाजायज तरीके से खाता है। आप करप्शन को कम नहीं करना चाहते हैं उसको ग्लोबल-फिनोमिना कह कर लीगलाइज करना चाहते हैं, उसकी परमीशन देना चाहते हैं। आपके यहां जो एडल्ट्रेशन हो रहा है उसकी वजह भी यही है। आपकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों को प्राफिट नहीं होता है, जब कि एडल्ट्रेशन से बहुत ज्यादा प्राफिट होता है— इसलिए वे एडल्ट्रेशन करते हैं। जैसे पिछले दिनों केस्ट्राएल का मसला पकड़ा गया, बीफ टैलो का मसला पकड़ा गया।

मेरे पास हरीश रावत साहब का पर्चा आ गया है कि खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, लिहाजा मैं अपनी तकरीर यहीं खत्म करना चाहता हूं। मेहरबानी करके इनपुट्स की कीमतें घटाइये जिससे किसान को फायदा हो और वह प्राफिटेबिल चीजें पैदा कर सके और लोगों को दे सके।

شری رشید مسعود (سہارنپور) محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ جو آدمی سو رہا ہو اس کو تو جگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور کسی نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن جو آدمی جاگ کر بھی سو رہا ہو اس کو جگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سرکار جاگ رہی ہے لیکن یہ لوگ اپریشن دے رہے ہیں کہ سو رہی ہے۔ ہم اس کو کیسے جگا سکتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔

۱۹۸۰ء میں کانگریس (آئی) کی سرکار نے محترمہ پرائم منسٹر صاحبہ نے اور مختلف وزراء صاحبان نے کہا تھا کہ ہم صرف پیاز کی قیمت پر جیت کر آئے ہیں اور سینٹر میں سرکار بنا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایک بار سے زیادہ بار یہ کہا تھا کہ ہمارا فرض یہ ہوگا کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کریں اور کنٹرول ہی نہ کریں بلکہ ان کو نیچے لانے کی کوشش بھی کریں۔ شری ہریش راوت کی تقریر سن کر مجھے تعجب سے زیادہ افسوس ہوا۔

شری نارائن چند پراشر (ہمیر پور) اکیلے سونے کی بات ہے۔ بی جے پی کے ساتھ سوئیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔

شری رشید مسعود : بی جے پی والے تو سوتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں بھی جگا کر رکھیں گے یہ ۱۹۸۰ء میں آپ نے سرکار سنبھالی۔ اس وقت کے منسٹر صاحب نے بڑے زوردار الفاظ میں ہاؤس میں کہا تھا کہ ہمارا مقصد نہ صرف یہ ہوگا کہ قیمتوں کو بڑھنے سے روکیں بلکہ قیمتوں کو نیچے ہم لائیں گے۔ ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کی ذمہ داری آپ نے جنتا اور لوک دل کی سرکار پر ڈالی تھی۔ ہریش راوت صاحب کہہ رہے تھے گو کہ ان سے پہلے جو منسٹر تھے وہ بھی کہتے تھے اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور دوسرے منسٹر کو لاکر انچارج بنا دیا گیا تھا کیونکہ انھوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔

ڈاٹا آپ نے نہیں دیکھا ہے اس لیے آپ کو علم نہیں ہے۔ جنتا لوک دل کی سرکار کی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں کنزیومر انڈیکس کی بات کرتا ہوں۔ جنتا سرکار دو سال پانچ مہینے حکومت میں رہی۔ مارچ ۱۹۷۷ء میں یہ انڈیکس ۳۱۴ تھا اور جولائی ۱۹۷۹ء میں جب جنتا سرکار یہاں سے ہٹی تو ۳۵۰ تھا۔ جولائی سے دسمبر ۱۹۷۹ء تک پانچ مہینے لوک دل کی سرکار رہی۔ اس پانچ مہینے میں ۳۵۹ پوائنٹ سے لے کر اس نے ۳۷۱ پوائنٹس پر اس کو چھوڑا۔ پورے پانچ مہینے میں بارہ پوائنٹس کا ہی اضافہ ہوا۔ اگر اس کو پورے مہینے کے لحاظ سے دیں گے تو جنتا سرکار کے دو سال پانچ مہینے میں ہر مہینے اوسط کنزیومر پرائس انڈیکس ۱.۲۸ بڑھا اور لوک دل کی سرکار کے پانچ مہینوں میں ۱۷ فروری ۱۹۷۱ء

کو یہاں فائننس منسٹر نے کہا تھا کہ ۱۹۷۱ء میں ایسا سوکھا پڑا جو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑا تھا اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ان پانچ مہینوں میں تین پوائنٹس ہی ہر مہینے اس میں اضافہ ہوا۔ اور گورنمینٹ ویٹ ورکس کے چار سال کے دوران انھوں نے جب سرکار سنبھالی تھی تو اس وقت کنزیومر پرائس انڈیکس تھا ۱۷۳ اور آج وہ بڑھ کر ۳۴۵ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر مہینے ۵٫۳۱ پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے کنزیومرس پرائس انڈیکس میں۔ ہریش راوت جی بار بار کہہ رہے تھے کہ جنتا سرکار اور لوک دل سرکار کے زمانے میں کیا تھا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے زمانے میں اور آپ کی سرکار کے زمانے میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔

یہی نہیں ۱۹۸۱ء کی تقریر میں فائننس منسٹر نے کہا کہ ہول سیل پرائس انڈیکس اپنی جگہ پر رک گیا ہے لیکن کیا کنزیومر پرائس انڈیکس رکا جس سے عام آدمی کا تعلق ہے۔ انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جب جلدی قیمتیں گرنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اپوزیشن سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں ہم آنکھ میچ کر آپ کی تعریف کرتے چلے جائیں۔ تو یہ ناممکن ہے۔ ہمارا تو فرض ہی ہے کہ سرکار کی غلطیاں بتائیں لوگوں کی تکلیفیں آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ نے چار سال میں کوئی تعریف کا کام ہی نہیں کیا۔

قیمتیں بڑھیں انسٹی ٹیوشن برباد ہو گئے لا اینڈ آرڈر تباہ کر دیا کیا ان سب کی ہم تعریف کریں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جنتا سرکار کے زمانے میں شام کو چار بجے کے بعد دلی میں عورتیں نکلتے ڈرتی تھیں لیکن کانگریس سرکار کے زمانے میں پانچ بجے کے بعد دلی شہر میں آدمی نکلتے ڈرتے ہیں۔ کیا اس کے لیے آپ کی تعریف کریں۔

(انٹرپشن)

آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اگر یہ بات آپ کہنے لگیں کہ ہر چیز آسانی سے مل رہی ہے کوئی قیمتیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ایک قصہ یاد آگیا دو صاحب میں لڑائی ہو رہی تھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور دوسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں بڑھ رہی ہیں۔ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ قیمتیں نہیں بڑھ رہی ہیں انھوں نے کہا جب میں بازار جاتا ہوں تو سب چیز مل رہی ہے دوسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ملتی ہی نہیں ہیں جب گھر جاتا ہوں تو پریشانی ہی سامنے نظر آتی ہے۔ تو جو صاحب کہہ رہے تھے کہ قیمتیں نہیں بڑھ رہی ہیں انھوں نے کہا کہ اگر آپ کو چیزیں نہیں ملتی تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے صدر بازار چاندنی چوک۔ اگر آپ کو خریدنا ہے۔ تو ٹی وی اور ریڈیو سے خریدئے۔

آپ کی قیمتیں بڑھنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کسان جو چیزیں پیدا کرتا ہے ان میں جو ان پٹس وہ استعمال کرتا ہے ان کی قیمتیں آپ نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو بالکل منافع نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھئے فرٹیلائزر میں آپ نے کیا کر دیا ہے ۶۰ پرسینٹ سے زیادہ بڑھا دیا ہے......

ایک مانئے سدسیہ: اس میں تو کم ہوا۔

شری رشید مسعود: کم کرنے کا کیا طریقہ ہے پہلے سو پرسینٹ بڑھا دیا اور اس کے بعد ۲۵ پرسینٹ گھٹا کر آپ یہ کہیں کہ ہم نے ۲۵ پرسینٹ گھٹا دیا ہے اسے گھٹانا نہیں کہا جا سکتا۔ ان پٹس کی قیمتیں اتنی گھٹائیے جس سے ہر چیز کسان کو مارکیٹ میں سستی ملے جیسا جنتا پارٹی کے دور میں ہوتا تھا۔ . .

شری ہریش راوت: خدا سے ڈرئیے اتنا بڑا ** نہ بولئے۔

شری رشید مسعود: کیا میں نے غلط کہا ہے۔ آپ نے ان پٹس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں پانی کی قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی قیمت بڑھائی ہے فرٹیلائزر کی قیمت بڑھائی ہے لگان آپ نے بڑھایا ہے ان سب کا نتیجہ ہے کہ کسان جتنی چیزیں پیدا کرتا ہے الٹی میٹلی ان کی قیمتیں بڑھیں گی جب کہ ان میں کسان کو کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا ہے۔

کسان جو انپٹس استعمال کرتا ہے ان کی قیمتیں کم کیجئے تاکہ اس کو سستی مل سکیں اور اس کو فائدہ ہو سکے۔ آج نہ کسان کو فائدہ ہو رہا ہے اور نہ کنزیومر کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سارے ملک میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ پرملا جی نے کہا تھا کہ جو آپ کا ڈسٹری بیوشن سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو گیا ہے۔

**Expunged as ordered by the Chair.

شری ہریش راوت : کمپلیٹلی ۔

شری رشید مسعود : مکمل طور پر ۔

شری ہریش راوت : اسکو کم کیجیے ۔

شری رشید مسعود : تھوڑا سا کم کر دو ۔ راوت جی میرے دوست ہیں ۹۵ پرسینٹ فیل ہو گیا ہے ۔ آپ کی یہ شاپس لوگوں کو صحیح چیزیں نہیں دیتی ہیں بلکہ ایڈلٹریٹڈ چیزیں آپ کے سپر بازار میں مل رہی ہیں ۔ اس پر کون کنٹرول کرے گا ۔ اس میں اپوزیشن سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں تبلائیے ۔

کرپشن کیوں بڑھ رہا ہے ۔ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ملازم پیشہ لوگ ہیں جن کی فکسڈ سیلری ہے ان کی بیوی تیس دن کا اپنا بجٹ بناتی ہے لیکن پندرہ دن گزرتے گزرتے قیمتوں میں پچاس ساٹھ پرسینٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بجٹ فیل ہو جاتا ہے باقی کے پندرہ دن وہ کہاں سے کھائیں گے ۔ لہذا وہ ناجائز طریقے سے کھاتا ہے ۔ آپ کرپشن کو کم نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو گلوبل فینومینا کہہ کر لیگلائز کرنا چاہتے ہیں اس کی پرمیشن دینا چاہتے ہیں ۔ آپ کے یہاں جو ایڈلٹریشن سے ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے ۔ آپ کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کو پروفٹ نہیں ہوتا ہے جبکہ ایڈلٹریشن سے بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اس لیے وہ ایڈلٹریشن کرتے ہیں ۔ جیسے پچھلے دنوں کیسٹر آئل کا مسئلہ پکڑا گیا بیف ٹیلو کا مسئلہ پکڑا گیا ۔

میرے پاس ہریش راوت صاحب کا پرچہ آ گیا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو ۔ لہذا میں اپنی تقریر یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے ان چیزوں کی قیمتیں گھٹائیے جس سے کسان کو فائدہ ہو اور وہ پروفیٹیبل چیزیں پیدا کر سکے اور لوگوں کو دے سکے ۔

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। यह बात सही है कि जब महंगाई बढ़ती है तो खास कर जो निश्चित आय वाले हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी, कल कारखाने के कर्मचारी अथवा समाज के कमजोर वर्ग के लोग, हरिजन और आदिवासी, मैं उनमें लघु और सीमान्त कृषकों को भी मिला देता हूं—इन सब को बड़ी कठिनाई होती है।

इसमें कोई शक नहीं है कि मंत्री जी ने 18 अगस्त को स्टेटमेंट इस सदन में दिया था वह सही वस्तुस्थिति बताता है। माननीय मन्त्री जी ने तथ्यों को छिपाया नहीं है। जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हैं तो हमें उस पृष्ठभूमि को देखना होगा जब दोबारा 1980 में हमारी पार्टी सत्ता में आई थी। आपको याद होगा कि 1979 में सूखा पड़ा था उसके बाद जब हमारी पार्टी सत्ता में आई तो उसने होलसेल प्राइसेज को कम करने का प्रयास किया। 1980-81 में जो होलसेल प्राइसेज 18.2 प्रतिशत बढ़ीं वह 1981-82 में 9.3 प्रतिशत बढ़ीं और 1982-83 में 2.5 प्रतिशत ही बढ़ीं। यह बात सही है कि देश में कांस्ट्रक्शन की कीमतें ऊपर चढ़ीं लेकिन सरकार ने इंफ्लेशन को रोकने का पूरा प्रयास किया। सरकार ने लचीली मानेटरी पालिसी अख्तियार की। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी प्रयास होने चाहिए थे उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। हमारे लोकदल और जनता पार्टी के साथी क्या इस बात को भूल गए कि उस वक्त प्याज क्या भाव था और नमक क्या भाव था तथा मिट्टी के तेल और पेट्रोल के लिए कितनी लम्बी लम्बी लाइनें लगा करती थीं? आपने ऐसी नीति अपनाई थी जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि चीनी की बड़ी परेशानी हो गई। वह तब दूर हुई जब हमारी पार्टी की सरकार ने आकर गन्ना उत्पादन की व्यवस्था की। आपने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए गलत नीतियां अपनाई। आपको मालूम होना चाहिए कि 1978 में कई सालों के बाद बड़ा अच्छा मौसम रहा था। लेकिन इधर पिछले तीन सालों से लगातार सूखे और बाढ़ की स्थिति चल रही है। इस साल तो 5 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सूखा है। इसके अलावा आपको पता ही है कि तूफान से कितना नुकसान उड़ीसा में हुआ। मद्रास में भी सूखा है। कई जगह ओले पड़े जिनसे बड़ी क्षति पहुंची। इस साल 31 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में आपको देखना चाहिए। इस साल फिर भी हमने रिकार्ड गेहूं की पैदावार की है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब गेहूं या चावल के दाम कुछ बढ़ते हैं तो मैं उससे चिन्तित नहीं होता हूं क्योंकि उससे हमारे किसानों की आशायें कुछ बढ़ती है और वह कुछ अधिक पैदावार करने के लिए उत्साहित होता है। लेकिन जब उन चीजों के दाम बढ़ते हैं जिनकी आवश्यकता किसानों को होती है तो मैं अधिक चिन्तित होता हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों तथा फैक्टरियों द्वारा उत्पादित माल के दामों में संतुलन लाया जाए। हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य जब किसानों में जाते हैं तो कहते हैं ढ़ाई सौ रुपया क्वींटल गेहूं का दाम होना चाहिए लेकिन शहरों में कहते हैं कि सरकार कितना महंगा गेहूं दे रही है। इसलिए वस्तुस्थिति को भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही कुछ कठिनाई पैदा हुई प्रधान मंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव दिया कि हर ढ़ाई हजार यूनिट्स पर एक राशन की दुकान खोली जानी चाहिए लेकिन यह बात भी सही है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स सेन्टर की गाइडलाइन्स का पालन नहीं करती हैं। आज भी दूरदराज के गांवों में राशन की दुकानें नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में ही यह दुकानें रह जाती हैं। दूर दराज के इलाकों में जो हरिजन आदिवासी हैं उनके लिए ब्लाक से कार्ड तो बन गए हैं लेकिन उनको राशन नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल में ऐसी स्थिति है।

इसके अलावा हमारी सरकार ने स्मगलर्स, प्राफिटीयर्स, होल्डर्स और ब्लेकमार्केटीयर्स की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सलाह दी कि उनके खिलाफ मीसा का प्रयोग किया जाए।

हमारे कम्यूनिस्ट, सी० पी० एम० के जो साथी हैं, वे उसको लागू नहीं करते हैं। कितनी दया है, उन लोगों के प्रति, इनके मन में जो समाज के एन्टी सोशियल एलीमेंट हैं। इस सारी पृष्ठभूमि को भी देखना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा इनकी सरकार के समय में आर० एस० एस० और जनसंघ के लोगों को दुकानें देना शुरू कर दिया था, अन्धाधुन्ध तरीके से और एक ब्लेकमार्केटीयर्स का तमाशा सा बन गया है। वे लोग अर्गेनिजेशन को चन्दा देने वाले लोग हैं। ये उनकी सहायता करते हैं जो समाज के शत्रु हैं। हमारी सरकार और हम लोग विरोध पक्ष से सहयोग इस दृष्टि से चाहते हैं कि आप ऐसे तत्वों को पकड़वाने में सहयोग दें। उनको बचाने का प्रयास न करें। यही मुख्य आधार माननीय मंत्री जी का है!

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर प्राइस राइज को रोकना है तो दो-तीन मुख्य बातों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो सीमान्त और लघु किसान हैं, जब हारवैस्टिंग का समय आता है, तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे को-ओपरेटिव के माध्यम से हो, उसी समय किसानों के गल्ले को खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि उनको लगान देना पड़ता है, कर्ज चुकाना पड़ता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल जाए। विरोध पक्ष के ही शासन काल में ही किसानों को अपने खेतों में गन्ने को जलाना पड़ा था और कोई दस पैसे में भी उसको उठाने वाला नहीं था। हरियाणा और पंजाब में कपास की कीमत के बारे में आपको पता होगा। लोकदल के ही शासन काल में, चौ० चरणसिंह जो किसानों के मसीहा समझे जाते रहे हैं, जो गरीबों और मजदूरों की बात करते हैं ही जो जब इनके समय में कोई मांग आती रही है, तो वह ठुकराई जाती रही है। यदि इन चीजों की तरफ दृष्टि डालें तो हमने बहुत से अच्छे काम किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सटेंड किया है। इस सिस्टम को सही तरीके से चलाने में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। मैं शासन को यह भी बताना चाहता हूं कि जिन सामानों की कीमतें बढ़ी हैं···(**व्यवधान**)···

श्री रशीद मसूद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि लोकदल की सरकार के समय में किसानों को गन्ने की कीमत मिलनी शुरू हुई थी।···(**व्यवधान**)···

श्री हरीश रावत : मान्यवर, श्री रशीद मसूद

प्राइटवेली मुझे बता रहे थे कि चौ० चरणसिंह ने देश की इकानामी को रूइन किया है। ···(व्यवधान)···

श्री रामप्यारे पनिका : देश की स्थिति को देखते हुए मैं आपसे मांग करता हूं कि चाहे गैर सरकारी या सरकारी नौकरियों में लोगों को महंगाई भत्ता समय से देना चाहिए। दूसरे—देहात के लोग हैं, गरीब और मार्जिनल किसान हैं, उनको निश्चित तरीके से प्रति माह राशन मिलना चाहिए। जैसे तेल की बात है, रेपसीड आयल की बात है, जब खाया जाता है, तो लगता नहीं है कि सरसों का तेल खाया जा रहा है। अनेक प्रकार की मिलावट हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। आज बीफ-टैलो की बात कही गई है, मैं समय को देखते हुए इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो समाज के शत्रु हैं, मिलावट करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, होर्डिन्ग और स्मगलिंग करते हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो हमारे सी० पी० एम० के साथी बैठे हैं, उनको इस बात से सहमति प्रकट करनी चाहिए और इसको लागू करवाना चाहिए। बिना डर और बिना भय के यह काम होने वाला नहीं है। समाज के विरोधी तत्वों को पकड़ने की आवश्यकता है।

इसी के साथ मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह इस समस्या से सख्ती के साथ निपटेगी और कठोर कदम उठाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, in his statement to the House, my hon. friend, the Finance Minister has been moderate in his claims. He has claimed that there has been some moderation in the prices of some commodities for some time. He does not deny that the whole sale price index as well as the consumer price index is constantly on the climb ; he only says that he has been able to regulate the gradient and control the gradient for some time ; he does not hold forth any promise that the present trend will continue. Therefore, in a sense there is an incipient confession of lack of confidence about his own ability to control prices in the statement that he has made before the House.

The hon. Finance Minister may be well-known for the nimbleness of his fingers when he picks the pockets of the tax-payers. But there are certain figures, which cannot be juggled away even by the nimble fingers that my hon. friend has.

The wholesale price index has been continuously rising during the last six months, except for a week or so in April-May. The consumer price index has been continuously rising at a much faster rate than the wholesale price index. The hope of the Finance Minister that the low rate of increase of the wholesale price index would be reflected in the consumer price index has been belied. It appears that the infection has spread from one to the other, or both were simultaneously infected by my hon. friend's policies. Both the wholesale price index and the consumer price index have been ascending uninterruptedly. In fact, the ascent has been more steep in the case of essential commodities that affect the common man, the poorest of the poor, like food, cereals, rice, vegetables, milk, egg, fish, meat, tea and kerosene. You have raised more revenue through increasing administered prices in the last three years than through additional measures of taxation.

I do not deny the value of the wholesale price index. I am sure my hon. friend will agree with me when I say that there seems to be a dual process of distillation and rarification of the reality. The wholesale price index does not reflect the impact of the inflation on the common man ; to some extent the consumer price does. But, I am afraid, even the consumer price index cannot convey the real impact of inflation on the common man, especially on the retail prices of essential commodities. My distinguished colleague, the hon. Member for Bombay Central North very ably referred to this point. I do not, therefore, have to tarry there.

But I would like to point out to my hon.

friend two things. First of all, when he makes a point to point comparison, perhaps he thinks that he is on a very strong wicket. But these points are not permanent points in terms of time, in the parameters of time. So, before the ink is dry on the statement that he placed before the House, he is belied by the increase in the consumer price index as well as the wholesale price index. I am afraid, I cannot agree with him when he says that after May there has been considerable moderation, and the moderation continues to remain so.

Sir, with your indulgence, I would like to refer to a statement that was made by the hon. Minister of Food about the percentage variation in the wholesale prices of selected commodities during the last six months. These are not culled from any newspaper, these are not concocted by the opposition, these are figures which the hon. Food Minister placed before the House—I shall not read everything—: Rice 13 per cent ; bajra 17.4 per cent ; maize 16.4 per cent ; ragi 14.8 per cent ; moong 20 per cent ; potatoes 53.4 per cent ; oranges—let us not talk of them ; should we ?—95.2 per cent. Kerosene—6.4 per cent ; tea, which is the common man's drink,—to this even my friend from Garhwal would agree—56.8 per cent ; maida—12.6 per cent ; gur—28.2 per cent ; groundnut oil 7.6 per cent ; cement 10.3 per cent. And as you must have seen in the newspapers there is a threat in Delhi that the price of bread will go up by 25 per cent.

Apart from these figures which the hon. Minister has given, if you look at the prices of commodities in the different parts of our country—my hon. friend will, of course, say that it is very difficult to give figures about each State or each city, but I have a right to talk about my constituency which is very near to his constituency in the other House,—Sir, if you look at retail prices in Bombay, you will see that in one year, rice has gone up by 55.6 per cent, wheat 25 per cent, jowar 13.3 per cent, potatoes 20 per cent, onions 33 per cent, tea 25 per cent etc. I quote these figures only to show that the statement mady by the hon. Minister of Food as well as these figures show a dangerous trend. For my hon. friend to hug the wholesale price for comfort is, therefore, to hug a double distilled illusion, and to allow the hallucination of rarefied figures to extinguish his touch with reality.

Now, my hon. friend can claim that there are two ways in which this problem can be tackled. I shall quote : "Higher production and adequate availability of the commodities are the most effective answers to the problem of inflation". No question. Increasing production and immunising the consumer through the public distribution system are his recipe. Agreed. The next step is the mopping up of excess liquidity in the system by raising the cash reserve ratio.

Sir, the goods and services in the economy must bear a certain healthy relationship with the volume of money in circulation, but the Government's acts of omission and commission have made the most spectacular contribution to the upsetting of this balance. The rate of growth of industrial production, my hon. friend will agree, has fallen, in spite of his efforts, not merely because of drought, from 8.3 per cent to 3.2 per cent or so, but because of the failure in infrastructural services, and the under-utilisation of installed capacity. My hon. friend might have read the other day an observation by the FICCI or so that under-utilisation is responsible for loss of production to the tune of Rs. 10,000 crores which might have yielded the Government Rs. 3000 crores imaginary revenue. The under-utilisation of installed capacity in the generation of electricity alone, the World Bank has said, has led to a loss of Rs. 60 million in terms of production. Sir, I shall leave it at that.

But what are these acts of omission and commission ? My hon. friend from Bombay Central (North) and Calcutta North (East) have referred to these. Firstly, the overall budgetary deficit of the Centre and the States has been of the order of nearly Rs. 10,000 crores. I am not shocking the hon. Minister, I hope. I looked up the *Economic Survey* before coming in. And excluding the estimate for the current year it is Rs. 7,400 crores plus Rs. 1,500 crores or whatever it may turn out to be for the last year.

Secondly, the Government has increased

its reliance on indirect taxation raising the percentage of indirect taxation to well over 85 per cent. Thirdly, the Government has made no appreciable effort to reduce wasteful and pompous expenditure. I shall not refer to the ASIAD. But in answer to a question of mine, figures were given of the difference between the estimated expenditure on the building of the stadia and the complexes and the actual expenditure, and as my hon. friend might very well know, the difference has comes to more than Rs. 500 crores. Fourthly, the Government has not been able to check smuggling which, it is estimated, is of the order of nearly Rs. 7000 crores. Neither he nor I can claim expertise on this subject and, therefore, I do not think I should hold him to anything.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : I am prepared to give the expertise to you.

SHRI RAVINDRA VARMA : Well, I know. But my friend, you know very well that in the State that you have the honour to represent in the other House, the President of your party accused a Minister of the Government of that State belonging to your Party of smuggling, and harbouring smugglers and holding bricks of smuggled gold, and challenged the Government to raid his house. Whether you did it or not, you know better than I do.

The second point he has made is about the control of liquidity. It is a very important question. It is no exaggeration to say that the Government seems to have taken its hand off the rudder, the steering wheel. Liquidity, as my hon. friend has pointed out, lies not only in the money available with the banks. Black money, is a very important source of liquidity. Here again my hon. friend may not be able to talk with authority on black money, but certainly he is aware of the estimates Rs. 10,000 to 40,000/- crores or Rs. 20,000 to Rs. 40,000 crores. The Voluntary Disclosure Scheme, demonetisation of notes of high denomination, special bearer bonds—first innings, second innings, have not led us to a solution of the problem. Like Ashoka on the battle field of Kalinga, after their electoral victory my hon. friend's Government, seems to have been overcome by infinite compassion for the barons of black money. They dare not touch them. If you are earnest about controlling black money, I would appeal to you to appoint a high powered commission which will go not only into how to tackle black money after it has been generated but also how to plug the loopholes from which it flows. If the Government is earnest, I hope they will do it. If you do not control black money, then how can you control the volume of money in circulation ? If you plug a certain hole in the white money area, then black money will flow into fill up the vacuum. My hon. friend knows this much better than I do.

He talks of bank credit and raising the cash reserve ratio from 8 to 8.5. But he knows very well that a good part of bank credit goes to the Government, and another part goes to the commercial sector which includes the public sector. For lack of time I do not quote figures in detail. But I must point out to him that in the full year 1982-83 the increase in the Government share of bank credit was 15%, and that in the commercial sector was 15.06%. But from 31.3.1983 to 1.7.1983 the increase in the Government share was 8.1%, while that of the commercial sector was 4.1%. For lack of time I do not go further into it. My hon. friend will realise that squeezing the commercial sector alone, without any similar effort on the part of the Government sector, may only mean the generation of recessionary trends and further under-utilisation. The effect of IMF conditionalities may result in your maintaining the ceiling of credit but your sectoral allocations of creditmay go awry as they have already gone awry, as my hon. friend knows very well.

I have to refer to more points. One is the role of administered price. In the last ten years administered prices have gone up by 215%, while free market prices went up by 137%. In 1980-81 after my hon. friends Government came, the whole-sale prices of all commodities increased by 16.7%, administered prices increased by 26.2% and their contribution to the general increase was 34.6%. In 1981-82 all commodities increased by 2.4%, administered price increased by 4.6%, making a 64.2% contribution to the total. In 1982-83 it is the same—4.4% and

4.6.% and 26%. There have been massive increases in the administered prices of all commodities which provide the base for infra-structure. My hon. friend knows the chain reaction that this causes all along the line. When you increase the prices of petrol and diesel, cement, steel, coal, fertilisers and the rates of electricity, freights and fares, the cost of essential goods and services soars up. If you raise administered prices but do not increase production, you end up with a high capital output ratio. 24% of the G.N.P. is invested to-day to achieve a growth rate of 2%.

I shall not refer to the steep rise in the prices of essential commodities. But I shall point out to my Rt. Hon'ble friend that out of 66 items that go into the consumer price packet, 49 items have registered a steep rise.

I shall conclude by referring to the public distribution system which is very important, as my hon. friend has pointed out. It seems that the number of shops are 28,000 or have been reduced from 29,000 to 28,000.

My hon. friend's colleague, the Minister of Food is not sugar-coated in his expression, as the hon. Minister of Finance is. He said that the Government could procure only 12.5% of the production. The demand on the public distribution system has increased because of the increase in the number of fair price shops, because of drought and because of the increase in the free market price. The demand is approximately 1.75 million tonnes per month. The Government's own estimate is 1.50 million tonnes but the supply is 1.15 million tonnes. Now, Sir, this means that a good number of people cannot avail of the services of the public distribution system. I am not referring to the question that my hon. friend from there referred to. The fact is that the public distribution system covers only a part of the population of this country, naturally in the utban areas and even in these public distribution outlets, you often find that you do not get rice, you do not get sugar and you do not get many of the commodities which are supposed to be distributed through that system. You know that there is a subsidy of Rs. 800 crores. The difference between the procurement price and the issue price of the consumers, on the basis of Rs. 30 per quintal for 12 million tonnes works out to Rs. 360 crores. Now, Rs. 800 crores and Rs. 360 crores total up to Rs. 1160 crores. In spite of this total expenditure, what is the benefit to the common man ? How many do we reach ? Will not my hon. friend agree that it is totally inadequate and incommensurate with the gravity of the problem and the dimensions of the problem that have been created because of inflation and the increase in prices !

I will conclude by referring to one factor. I have high respect for my hon. friend especially when he is of equable temper. He says that the Government has "responded by making arrangements to import some rice and to step up release of foodgrains and edible oil to the public distribution system." He creates an impression, he wants to create an impression in our minds that the public distribution is a veritable boon, and that it is the biggest insurance against the effects of inflation, that it will, therefore, enable us to pilot the boat of our domestic budget through the turbulent waters churned up by inflation. But what does the Food Minister say ? The Food Minister says, in answer to a Question in this House on 22nd August—is should be the latest thinking of the Government :

> "The allocations from the Central pool are only supplementary in nature and the needs of the population have to be met through free-market mechanism supplemented by the public distribution system."

SHRI SUNIL MAITRA : See, right hand does not know what left hand is doing !

SHRI RAVINDRA VARMA : Mr. Chairman, it means that my hon. friend, the Food Minister has washed his hands off like Pontius Pilate. I do not know who has poured the water. He says, I cannot underwrite the public distribution of the States ; You fend for yourself. We cannot give you. You find food from the open market." Will this not lead to increase in prices and will this not lead to driving the poor from the so-called public distribution system to the mercies of the open market ? If this will not, what will ? Therefore, I would request my hon. friend, though he has been very

moderate in the claims that he has made, to be more vigilant. He claims that he has been keeping watch. There is a famous line from Rabindra Nath Tagore :

"Much watching has made my sight dim."

I hope much watching and mounting futile vigil does not make his sight dim.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) : Sir, the rise in prices is a cause of serious concern for all sides. But it is an irony of the time that the friends from the Opposition side do not even welcome the good measures adopted by the Government to contain the price rise. Such a good measure as the effort to mop up liquidity has also not pleased Mr. Varma.

SHRI RAVINDRA VARMA : Professor, I said, "It is not adequate". I did not say, "It is not good".

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : We think it is adequate and the decision taken on 22nd August, 1983 by raising it up to 8% ratio is a good thing that has been done. Is it adequate or not, time will tell. But your attempt is to see in it an attempt to squeeze the commercial sector and because of more of the expenditure, more of the investment on the public sector is hardly a point that can be considered as a valid criticism. So, I would welcome the step taken by the hon. Minister.

Similarly, two or three other steps have been announced by him, an attempt to import rice and to put it in the public distribution system, reduction in the price of fertiliser by 7.5 per cent and increase in support price in certain cases so that that may lead to increased production. These are all the attempts that the Government have to make. But there are many other things which have to be done by the people at large.

Our economy in this country is primarily dependent upon seasonal factors, upon the vagaries of nature and most often upon the whims of our friends on the other side. Whereas a drought has been there, floods have been there, and all these are adversely affecting our economy and, therefore, in a way contributing to the price rise in this country, on the other side, the agitations are also contributing in no less a measure to the price rise. I would just refer to one point. On 17th June, in the north-west India, the prosperous States like Punjab and Haryana were subjected to the cancellation of trains. As many as 37 trains were-cancelled for one day and again on 29th August, there is another attempt. Sometimes, there is an attempt to immobilise the economy of this country and there is another attempt also in that direction. So, all these attempts are to be weathered by our economy which is dependent on vagaries of nature. In spite of this, we are happy, not to the extent to which we are happy, but we are contented and satisfied that the efforts of the Government are in the right direction.

Our appeal to the friends on the opposite side is that they should also see as to what will be the effect of paralysing the system of transportation for such a long period of time and subjecting the entire economy of our country and the entire market mechanism to strain which our economy will not be able to bear.

Of course, there is much criticism against the public distribution system. Nobody on this side claims that it is hundred per cent efficient and hundred per cent perfect. But it is a relevant point that we have to consider. Basically, the decisions taken by the Government, when it was their Government, are also responsible for the rise in price. It has been stated by the hon. Minister in his own statement made on 18th August that the gold that was auctioned, 13 tonnes of gold that was auctioned, for Rs. 86 crores, would have been worth Rs. 220 crores in December, 1980. You think of the amount of loss. It may be notional, whatever it is. But it is there for you to see what harm you have done to our economy and the amount of loss subjected to our economy.

All these factors are responsible for the price rise. Let us look at the Economic Reviews which are available in the Parliament Library for the last 5 or 6 years as to which is the year when the price rise has been the sharpest. Everybody will agree that it was in 1979 that the price rise was the sharpest. Therefore, we had to take over the economy in a bad shape and, from that bad shape, we

have ried to restore it to good shape or to whatever normal shape that we have been able to do.

The very fact that rains are not there ; the water level in the lakes has gone down and the generation of electricity from the hydel sources is not enough, all this is a strain on our economy over which neither they nor we have any control. If the rains do not come, if the water level goes down, if the generation of electricity falls below the normal level, is it the fault of the Government ? It is the seasonal strain that we have to bear.

Similarly, there are other things also. If there is a drought, if there are floods, it is the crop that suffers. You look at our areas, in States like Himachal Pradesh where scab disease is there and the entire cash crop has gone away. It cannot be consumed. So, the prices have gone up and so on and so forth. This will affect the other cash crops like potato, etc. All these things are interlinked. It is not an isolated point that you can pick up one item and not another item.

What are the measures to be adopted ? I plead for an organised consumer cooperative movement because that is the only thing that can offset some of the pressures which are caused by anti-social activities like hoarding, faulty distribution system, a desire to mop up advantages caused by artificial scarcities and things of this type. Therefore, the Government has not only to ensure that they provide inputs to the farmer, and to the people on reduced prices or subsidised prices so as to increase production in the fields and the factories but also to see that the strains of this nature which are caused on the economy are also minimised.

Much has been said about the salaried section of the people. I also belong to this section and I feel that the strain, the pressure, put on the salaried classes of the people is the sharpest because they have a fixed income and it is they who are subject to this pressure.

But there are also millions of other sections of people who do not have any fixed salary. They do not get fixed wages. They do not have any kind of bread-winning hope and, therefore, they are the greatest victims of this kind of vagary in nature and the rise in prices. I would plead for them and any consumer cooperative movement that would develop in this country should take into account the interests of those who have to earn their bread every day without the hope of getting the bread the next day, because they have no insurance that they will get the bread the next day. They are not sure whether pressure from the opposite side will not force a strike on the factory, whether there will not be a lockout from a big shop, business or industry and they will be forced to migrate from one city to another in search of labour. Similarly, there is the effect of wheather on our economy. If the crops fail, a huge chunk of labour has to migrate from one part of the country to another in search of a job, in search of bread. That also has to be taken into account. Overall, this is a total picture which has to be controlled, which has to be regulated, which has to be kept in normal shape by the efforts not only of the Government but by the entire society and in this, our trade union movement has to play a dominant part. If the friends on the opposite side believe that trade union movement would mean only to look after the interests of the labour class, of the working class and to forget the effects of this on production and things of this type, if you think only of the salaried class or a chunk of the population to the exclusion of the other, you are not doing justice either to the society or to the economy. I would, therefore, plead that the distribution system should be so regularised that there should be a monitoring mechanism at the Centre. Why should we say that the States do not cooperate ? Well, if the Centre gives the money, is it not a part of the duty of the Centre also to see that the purpose for which the money is being given is being properly utilised ? And there is a cooperative mechanism. I do not call that a centralised monitoring system. I call for a cooperative effort in which representatives of the States may also be there. But let us see that the things which are meant for the poor and for the farflung areas reach them. Similarly, let us see that the hoarding does not take away a big chunk of the profits. Things should normally be distributed among the people instead of being hoarded in a few pockets. Similarly, let us resolve if we are

serious in this effort, that no effort will be made to solve our political tangles by putting the economy to unnecessary pressures by immobilising the movements in the country or by stopping, or by reducing the various efforts which are made to increase production and to restore the economy to its healthy shape. The effort to reduce prices is common and a cooperative effort from all sides is required and in this the figures of expert nature which are given by Mr. Ravindra Varma are as necessary as the attempt to say some words of good advice to his friends like Sant Longowal. There is no use stopping all the movement of trains because that will also increase prices. It is very good that trains go on moving so that the prices are also at a normal level and there would not be increase. If only they have sense and if politics are not mixed with the economy, the interests of the common man would be served.

With these words, I appreciate the efforts made by our Government, by our Hon. Minister, for that purpose.

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने 18 अगस्त को सदन में जो वक्तव्य दिया, श्रीमती प्रमिला दंडवते ने उस पर चर्चा उपस्थित करके हमें उसमें भाग लेने का अवसर दिया है, उसके लिए उनको धन्यवाद।

जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा है, कीमतें बढ़ने के जो अलग-अलग कारण हैं, उनमें एक कारण यह है कि हमारे देश में किसानों को उनकी पैदावार के उचित दाम नहीं दिए जाते हैं और विदेशों से जो अनाज और दूसरी चीजें मंगाई जाती हैं, उनके ज्यादा दाम दिए जाते हैं। हमारे देश में कई इलाके ऐसे हैं, जहां ज्यादा पैदावार होती है और कई ऐसे इलाके हैं, जहां अनाज की कमी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण कीमतें बढ़ती हैं।

इसके अतिरिक्त सस्ते दामों पर मिलने वाली चीजों की दुकानों की कमी है। विशेष रूप से गरीब बस्तियां, किसानों और खेत-मजदूरों के इलाकों में ऐसी दुकानों की बहुत कमी है। जहां ऐसी दुकानें हैं भी, वहां से गरीब लोगों को माल नहीं मिलता, जो कि काला बाजार में चला जाता है।

प्रशासन चलाने वाले मंत्री, अफसर और व्यापारी, ये तीनों इस बात का ध्यान रख कर काम करते हैं कि चीजों के दाम कैसे बढ़ेंगे। मैं जिस इलाके से आया हूं, वहां वित्त मंत्री को "अर्थ मंत्री" कहते हैं। यदि अर्थ मंत्री अपने काम में सफल नहीं होते, तो उनको "अनर्थ मंत्री" कहते हैं, जिसका मतलब है असफल मंत्री। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के वित्त मंत्री महंगाई को रोकने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए उन्होंने 18 अगस्त को सदन के सामने जो स्टेटमेंट रखा, उसमें उन्होंने सफेद कागज पर काली सियाही में** कहा है।

सभापति महोदय : ये शब्द न कहिए। ये अनपार्लियामेंटरी हैं।

श्री जगन्नाथ पाटिल : उन्होंने असत्य कहा है। अपने वक्तव्य में वित्त मंत्री ने कहा है :

> "...from 14th may to 30th July, 1983, the wholesale price increased by 2.5 per cent which is significantly lower than the increase of 5.4 per cent during the same period in 1982-83 ;"

वित्त मंत्री ने पिछले साल से कम्पेयर करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। अगर उन्हें सही ढंग से कम्पेयर करना था, तो उनको 1979-80 के होलसैल प्राइस इन्डैक्स से इस समय के होलसैल प्राइस इंडैक्स को कम्पेयर करना चाहिए था। 14 जनवरी, 1980 को इन्दिरा कांग्रेस ने शासन सम्भाला, उस समय की कीमतों और इस समय की कीमतों में कितना फर्क है, मैं उसके कुछ नमूने पेश करता हूं।

19 hrs.

14 जनवरी, 1980 को चीनी का भाव 2.90

**Expunged as ordered by the Chair.

रुपए था और जुलाई, 1983 में वह 5.25 रुपए है। जो चावल गरीब आदमी खा सके, उसका भाव 1980 में 2.10 रुपए था, जबकि आज वह 4.70 रुपए है। ग्राउंडनट आयल, खाने के तेल का भाव, जिसमें सब चीजों की मिलावट की जाती है, 1980 में 10.30 रुपए था और आज वह 17.50 रुपए है। वनस्पति तेल का भाव, जिसमें सरकार की मेहरवानी से वीफ और वफेलो की चर्बी मिक्स की जाती है, 1980 में 13.50 रुपए था, जबकि आज वह 19.00 रुपए है। चाय की पत्ती का दाम 1980 में 22 रुपए पर-केजी था, जबकि आज वह 34 रुपये पर-केजी है। आप 1979-80 की कीमतों को सामने लाइये और जुलाई, 1983 की कीमतों को सामने रखिए तो माननीय मन्त्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसकी अस्लियत का पता माननीय सदस्यों को चल सकेगा। बाल कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि जनता राज में कीमतों में गड़बड़ हो गई। (**व्यवधान**) ट्रैजरी बेंचेज के माननीय सदस्य जब बात करते हैं तो बिना जनता पार्टी का नाम लिए उनका काम ही नहीं चलता है। मैं आपके माध्यम से ट्रैजरी बेंचेज के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है लेकिन 14 जनवरी, 1980 के बाद 43 महीने बीत चुके हैं— इतने समय में तो दो चार बार डेलिवरी हो जाती। इसलिए जनता पार्टी का नाम बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से उनको आर० एस० एस० को गाली दिए बिना खाना पचता नहीं है। महाराज शिवाजी के राज में मुगल सेना जब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाती थी और वह पानी नहीं पीते थे तो वे घोड़ों से कहते थे कि तुम को पानी में घनाजी सन्ताजी दीख रहे हैं क्या ?

सभापति महोदय : अब आप प्राइसेज पर आ जाइये।

श्री जगन्नाथ पाटिल : हमारे देश की 70 फीसदी जनता तो गांवों में ही रहती है और इस देश के आज पूरे 70 करोड़ लोगों को इस मंहगाई में किस तरह से जीना पड़ता है वह सारे लोग जानते हैं। जहां तक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, शहरों की दूकानों में तो कुछ चीजें मिल जाती हैं लेकिन सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से एक-एक चीज के लिए अलग-अलग दिन लम्बी-लम्बी लाइनें लगानी पड़ती हैं। अगर उन दूकानों को वह चीजें देनी ही हैं तो एक साथ ही दे देनी चाहिए ताकि जनता को उनको खरीदने में कुछ आसानी हो जाए। दूसरी तरफ गांवों में तो कोई चीज मिलती ही नहीं है। मैं जिस इलाके से यहां पर आया हूं वहां पर आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर राशन की दूकानें तो हैं, रिकार्ड पर है कि दूकानदार माल उठाते हैं—गेहूं, चावल, चीनी, आटा वगैरह—लेकिन कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलता है। अभी दो दिन पहले सदन में सरकार ने कहा था कि त्योहार के समय कुछ चीजें, चीनी वगैरह ज्यादा मिलेंगी लेकिन आज के "नवभारत टाइम्स" में मैंने पढ़ा कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी कम करने वाले हैं और चावल भी एक किलो कम करने वाले हैं। इस तरह से सरकार की पालिसी का पता ही नहीं चलता कि वह किस तरह से काम कर रही है। (**व्यवधान**)

अगर इन बढ़ते हुए दामों को नीचे लाना है, तो मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि किसानों को जिन चीजों की जरूरत होती है वह सस्ती दी जायें। आपने खाद की साढ़े सात प्रतिशत कीमत कम की है लेकिन पहले 60 प्रतिशत बढ़ा दी थी इसलिए अब साढ़े सात प्रतिशत कम करने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसानों को जो बीज दिया जाता है उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए और खेती के काम में जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है उनकी कीमत भी कम होनी चाहिए। जितना उनका पैदावार में खर्च होता है, उतना तो दे दीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक ही बात बताता हूं। एक किलो कपास से 15 मीटर कपड़ा बनता है। उसकी कीमत लगभग 90 रु० आती है। हमारे किसानों को 4.50 रु० किलो कपास दिया जाता है। मिल में काम करने वाला मजदूर जो सारी मेहनत मजदूरी करता है, एक किलो कपास से 15 मीटर कपड़ा बनाने में 90

रु० बन जाते हैं। उसका सारा खर्चा लगभग बीस रुपए आता है। 70 रु० बीच वाले उठाते हैं। अगर इसमें हम हिस्सा किसानों को देंगे, तो इसे देश के किसान अच्छे ढंग से अपना जीवन बिता सकता है। स्टेट्स में फूड जोन के लिए आपने बैन लगाया है। यदि इस बन्ध को उठायें तो कीमतें नीचे आ सकती हैं। सस्ते दामों की दुकानों को बढ़ाना चाहिए। मध्यम वर्ग के लोग जो शहर में रहते हैं, जैसे हमारे केन्द्रीय कर्मचारी हैं, प्राइस इन्डैक्स दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है, लेकिन इनकी ततख्वाहें नहीं बढ़ती हैं। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने गत 18 अगस्त को देश में मूल्य स्थिति पर जो अपना वक्तव्य दिया है, वह सही मायनों में वर्तमान मूल्य स्थिति की तस्वीर को उजागर करता है।

आज और इस वक्त जब इस सदन में देश की मूल्य स्थिति पर चर्चा हो रही है तो मेरा ख्याल है कि इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की नजर इधर लगी होगी और वे सोचते होंगे कि हमारे प्रतिनिधि जो आज मूल्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, देखें, इसका क्या परिणाम होता है।

जब मूल्य स्थिति की बात आती है, तो इससे प्रभावित होती है इस देश की गरीब जनता और मध्यम वर्गीय इंसान। अमीर लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास काले पैसे की कोई कमी नहीं है। बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े पूंजीपति या अमीर लोगों पर इस मंहगाई की मार का कोई असर नहीं होता है, चाहे चीजें कितनी ही मंहगी क्यों न हो जायें। असर पड़ता है सरकारी कर्मचारियों पर, किसान और मजदूरों पर और मध्य वर्ग के इंसान पर। जहां तक मूल्य स्थिति का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसका सीधा संबंध डिमांड और सप्लाई से होता है। मेरे बहुत से साथियों ने इस बारे में अपने-अपने विचार प्रकट किए है। कुछ लोगों ने इस सरकार को दोषी ठहराया है और कुछ लोगों ने पूंजीपतियों को और उन लोगों को जो देश में मुद्रास्फीति पैदा करते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं सरकार को पिता की संज्ञा देता हूं। जिस तरह से परिवार का मुखिया पिता होता है और पिता कभी नहीं चाहता कि उसकी औलाद को किसी प्रकार की तकलीफ हो, उसी तरह से सरकार भी कभी नहीं चाहती है और उसका सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है देश की जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। यह एक प्राकृतिक देन है, समाज में हर आदमी एक जैसी बुद्धि का नहीं होता है। एक जैसी विचारधारा नहीं होती है, एक जैसी अकल नहीं होती है। जहां पर लोग सरकार का साथ देते हैं, हर उस काम में जो वह जनहित के लिये करती है, जनता की भलाई के लिये करती है, वहां पर कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनको सरकार का हर काम गलत नजर आता है, उसके हर अच्छे काम में अड़ंगेबाजी लगाते है और गलत तरीके से उसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं।

मूल्य वृद्धि जो होती है उसके अनेक कारण हैं। सबसे पहली बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हू —कभी-कभी प्राकृतिक-विपदा ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से मूल्य अपने आप बढ़ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों बेतहासा बारिश हुई—इस से जितने साग-सब्जी के खेत थे, वे प्रभावित हुए हैं। साग-सब्जी ऐसी चीज नहीं है जिसका स्टोरेज किया जा सके या चार-छः महीने रखा जा सके, इसलिये जब भी ऐसी विपदा आयेगी, वह नष्ट होगी और नष्ट होने से उसका मंहगा होना स्वाभाविक है। आप इस वक्त के मौसम को देख लीजिये—देश में कहीं-कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है और कहीं-कहीं बाढ़ें आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत सी फसलें नष्ट हो गयी हैं और उनका सीधा असर मनुष्य की जीवनोपयोगी वस्तुओं पर पड़ा है, वे मंहगी हुई हैं।

मुद्रास्फीति की बात को लीजिये—जिस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से अपने

वक्तव्य में बल दिया है। यह हकीकत है कि आज मुद्रास्फीति रोकने में सरकार पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से सजग है कि उसको रोका जाय। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो यहां इस सदन में मंहगाई के लिये बड़ी-बड़ी चीखें भरते है, जोरदार शब्दों में कहते हैं, लेकिन उनको यह भी देखना चाहिये कि कम से कम उन्हीं की पार्टी के लोग या उनके समर्थक मुद्रास्फीति को रोकने में सरकार का कहां तक साथ देते हैं। अगर मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि जो लोग मुद्रा-स्फीति बढ़ाने में, चोरबाजारी करने, तस्करी और जमाखोरी करने और इस देश की अर्थ-व्यवस्था को चकनाचूर करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, मेरे उधर बैठे हुए बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनकी पार्टी ऐसे लोगों का खुलकर समर्थन करती है उन को सहयोग देती है। जब जमाखोरी होती है तो स्वाभाविक है कि चीजों के दाम बढ़ेंगे। इसलिये मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जखीरेबाजों, जमाखोरी करने वालों पर कड़ी नजर रखें, उनके भण्डारों पर छापे मारने में बड़ी से बड़ी ऐजेंसी और फोर्स को काम में लें। इस तरह के चोरबाजारी करने वालों, तस्करी करने वालों केखिलाफ जहाद बोलना चाहिये और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिये।

कीमतें बढ़ने का एक कारण उत्पादन है। जब उत्पादन घटता है तो मंहगाई का बढ़ना स्वाभाविक है, खासतौर से उन वस्तुओं का जो जीवन के लिये आवश्यक हैं। अगर उन वस्तुओं की पैदावार बढ़ाई जाय, सब लोग पैदावार बढ़ाने में सहयोग करें तो कीमतें घट सकती हैं। महंगाई दूर करना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है, मैं मानता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ पूरे समाज के सभी लोगों को इस बुराई को दूर करने में सहयोग देना चाहिये।

बहुत से लोगों ने काले-धन का जिक्र किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि काले धन से भी मंहगाई बढ़ती है। काले धन को रोकने के लिये हमारी सरकार ने बड़े-बड़े कानून बनाये हैं, फिर भी कानून की नजर से बच कर लोग काले-बाजारी का धंधा करते हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है—उन कालेबाजारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायें और इस रोग को दूर करने के लिये अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़ें। मंहगाई को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है इस सम्बन्ध में भी मैं अपने चन्द सुझाव देकर अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगा—

श्रीमन्, जहां तक उचित दर की दुकानों का प्रश्न है, अक्सर यह देखने में आया है कि जो देहातों में उचित दर की दुकानें खुलती हैं, उसमें अक्सर लोग बेईमानी करते हैं। चीनी हो, मिट्टी का तेल हो, दालें हों, सूजी हो या गेहूं हो या चावल हो, जो भी खाद्यान्न हैं, इनको लोग सही तरीके से पब्लिक में वितरित नहीं करते हैं और वहां के दुकानदार बड़े-बड़े स्टाकिस्टों से मिलकर उस से पैसे बना लेते हैं और अपनी जेब में रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि फेयर-प्राइस शोप्स नहीं खुलनी चाहिए बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और खास तौर पर उन इलाकों में बढ़ाई जानी चाहिएं जहां पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं और पहाड़ों पर रहने वाले लोग रहते हैं, और दूसरे गरीब तबके के लोग रहते हैं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि नेफेड जैसी ऐजेंसियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इस तरह की ऐजेंसियां राज्य स्तर पर बनानी चाहिएं क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि प्याज जब 4-5 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी और अंडा बहुत मंहगा हो गया, तो नेफेड ने अपनी मोटर-वेनों में इस तरह की सामग्री भर-भर के सस्ते दामों पर इनको बेची और इससे जनता को काफी लाभ मिला। इसलिये इस तरह की एजेन्सियों को बढ़ावा देना चाहिए और जो पब्लिक डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम है, इसको और कारगर और प्रभावशाली बनाना चाहिए।

जहां तक किसानों की बात है, उनको और

अधिक सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : Mr. Chairman, Sir, the economy of the country is in doldrum. The rate of price rise of all essential commodities in this country has virtually become uncontrollable and it is gallopping like an unbridled horse and the Indian economy is badly wounded. The purchasing power of the people is totally wrecked. I ask the Government : what are the drastic steps taken by the Government of India to protect the poor, the middle-class and the down-trodden for the last 35 years ? Truly speaking, the common man in this country are fighting for their survival. The public distribution in this country has become purely private distribution between the ruling party and the officials in Tamil Nadu. This fact is very well known to everybody. The fair price shops have become black-marketing centres and in Tamil Nadu they have become black-marketing shops. The whole-sale consumer price index revealed by the Government of India and the States throughout the country is only a paper Tiger. Price indices are having no relevance with the price level prevailing in this country. The real price is steadily sucking the blood of the poor people of this country. We say that ours is a welfare State. But the present ruling party of this country has not been able to provide cheaper variety of cloth for the poor for the last 35 years. Moreover, if it is available, it is not at all available even for meeting the minimum needs of the people. Then, Sir, essential food articles are not at all available to the common people at a cheaper price. The poor and middle-class people will have to pay for the essential food articles as the rich who can afford to pay. There is no rice, no shelter, no food, no cloth and no employment opportunity for the poor and down-trodden.

Still you say that ours is a Welfare State. Our great leader, late Mr. C.N. Annadurai, when he was the Chief Minister of Tamil Nadu, had once said : "Tap the Rich and feed the poor". But now what is happening today ? It is *vice versa* that is happening nowadays. We come across the instances of the poor becoming poorer and the rich becoming richer. Over the last 35 years or so, the poor have become impoverished and the rich are becoming constantly richer and wealthier in this country under the present regime. What has happened to the price of cement ? Do you think that the cement policy followed by the Government of India is a wise policy ?

The Government is following an unwise and unwarranted policy in respect of cement. The price of a bag of cement a couple of years ago was Rs. 25 or Rs. 35 in Madras as also in other parts of the country, but now this Government has fixed the statutory price of Rs. 62 per bag. Even then, I could not purchase a single bag in Tamil Nadu at Rs. 100. This is perhaps the condition everywhere. The policy of the Government in respect of cement is not only unwise, but it is also anti-people. As I told you, it was not possible for me to procure a bag of cement even in the black-market. We all know that black-market is rampant in this country in so far as cement is concerned. It is only because of the wrong policy of the Government.

Certain poll promises were made during the last elections in 1980, and it was stated that if Indira Gandhi came to power, they would reduce the price of gold, which is required for *'tali'*, *mangalsutra*, necessary for the ladies at the time of marriage. Now, what is the price of gold ? It has rocketed like anything. I am ashamed to say that we were also aligned with the ruling party at that time in 1980.

What happened to the 20-Point, 22-Point and 25-Point programmes announced by the Government ? Have you implemented those programmes ? No, you have totally and miserably failed to implement those programmes.

Now, let us have a look at the price level of rice. In Tamil Nadu in 1979-80, the ordinary rice which is consumed by the ordinary man was available at Rs. 2.50 per kg., now the price of that rice has risen to Rs. 4.50 per kg. The superfine rice which was

available in 1979-80 at Rs. 3.50 now sells at Rs. 7.50 per kg. And the price continues to rise steadily. The price of sugar has also gone up. Are you giving remunerative price to the sugarcane producers ? Are you giving remunerative price to the paddy growers ? We have discussed these problems repeatedly in this House, but the Government has become blind and deaf to these demands of giving remunerative prices to the farmers of this country.

Now, what about the price of cloth ? Can you say with your conscience that the poor man can purchase the cloth at the prevailing prices for himself and the members of his family ? He cannot. There is no check on the rising prices. The medicines, petrol, cement and all the items of daily use have gone up considerably. Can any poor man, in his life, think of purchasing a television set, which costs as much as Rs. 10,000 now-a-days. Everybody wants to glance through the newspaper in the morning, but its price has gone up during these days, because of the price rise in the case of newsprint. A common man thinks twice before getting a newspaper daily.

In Madras market this month tomato has been sold at Rs. 15 per kg., I am saying this in the name of God. It is unprecedented and unparalleled in the history. The price of the oil is Rs. 20 per kg., lady's finger Rs. 8 per kg. and carrot Rs. 7 per kg. The Government is not able to do anything in the case of controlling the price.

If the Government has gone a step further, it has gone two steps backward. That is the reason why the prices have gone up and still continue to go up. You claim that you have been able to contain the prices. In case you were able to contain the prices, why are the prices going up ? The Government should make an all-out effort to contain the prices. Everyday we are hearing from the Government that the production is going up. The prices are also going up. What is the reason ?

As the population increases, prices also increase. This is the reason the Government is giving. It may be admitted, but I ask what is the Government doing ? What is its duty ? I would like to know whether the Government has utilised all the water and natural resources in the country. The answer is no. So, it is the duty of the Government to have the maximum utilisation of the natural and water resources to meet the ends of justice and demands of the public. Sir, how much percentage of natural resource has been tapped so far ? It is only 33 or 35%. Some countries feel that population is wealth, but the Indians feel it is a sin. Why is it so ? It is because the Government is unable to deliver the goods to the people. That is the reason.

Now, what is the main reason for the rise in prices ? Why is the Government unable to control or contain the prices ? Sir, according to the Wanchoo Committee of 1969, the black-money even 20 years back was being transacted to the tune of 15,000 crores. Now, according to the reliable sources we find that Rs. 50,000 crores of black-money is being transacted. The black-money holders are running a parallel government against this democratic government. Therefore, I ask why this government has not been able to control these illegal and unconstitutional blackmarketeers The Government is unable to put its hands on the black-marketeers and it is actually afraid of putting its hands on the black-marketeers, hoarders, profiteers, smugglers, anti-social elements and anti-nationals because they are all sailing in the same boat.

Sir, there are three kinds of black-money operating in the country. One kind is that which is permanently existing in the country and which is not controlled by this Government. Another kind is one which is flowing inside the country from abroad and is not being checked. Yet another kind is that from Tamil Nadu it has gone out as a heavy amount to Singapore and to various other countries. I would like to know whether the Government will look into this matter. I say this because many a time this Government is blind to black-money, which is mainly responsible for the rise of prices.

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, प्राइस राइस के संबंध में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना

चाहता हूं। हमारी सरकार ने प्राइस राइस को चैक करने के जिस प्रकार के कदम उठाए हैं वे निश्चित तरीके से प्रशंसनीय हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता जो हमारे सदस्यों ने यहां पर रखे हैं लेकिन उनके बारे में कुछ खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं। आंकड़ों के बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं वे प्रशंसनीय हैं और माननीय वित्त मंत्री जी को और ज्यादा प्रयत्न करने चाहिएं ताकि मंहगाई बढ़ने के बजाए कम हो। लेकिन भारतीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और सी० पी० एम० के लोगों ने जो बातें कही हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस देश में महंगाई बढ़ाने के सबसे ज्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि जनता पार्टी के शासन में खुली फेयर प्राइस की सारी दूकानें इनके कब्जे में हैं। वहां से ये सारे काला-बाजार के धंधे करते हैं। इनकी पार्टी उनको प्रोत्साहन देती है। इसलिए कीमतें बढ़ने का ज्यादा से ज्यादा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है।

भारतीय लोकदल के लोग क्या करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि किसान जो उत्पादन करता है उसकी कीमतें बढ़ाई जाएं। हमारी सरकार ने कृपा करके गेहूं, चावल और गन्ने के दाम बढ़ाए, शक्कर के दाम बढ़ाए। दूसरी तरफ कहते हैं कि कीमतें ज्यादा हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। लोक दल के सदस्य समझें कि रा मैटीरियल की ज्यादा कीमत होगी तो निश्चय ही कीमतें सब चीजों की बढ़ेंगी, इसमें कोई दो रायें नहीं है।

सी० पी० एम० वालों को आप देखें। ये एक दाना चावल का प्रोक्योर करके नहीं देते हैं। बंगाल की सरकार एक दाना प्रोक्योर नहीं करती है, इनकी सरकार नहीं करती है और लाखों मन चावल हर महीने मांगते हैं जब हमारी सरकार बंगाल में थी तबका आप रिकार्ड देख लीजिये कि कितना चावल उसने प्रोक्योर करके दिया था। ये तो भारत सरकार से मांगते ही रहते हैं। यह इनका कोओप्रेशन है महंगाई को रोकने के लिए। जिस प्रकार का सहयोग हर पार्टी और हर सरकार को देना चाहिए, नहीं मिल रहा है। लम्बी चौड़ी यहां बहुत बातें की जाती हैं। मैत्रा साहब दुनिया भर की लम्बी चौड़ी बातें करके चले गए हैं लेकिन प्राइस राइज को किस तरह से चेक किया जाए इसके बारे में उन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया है। क्या है उनका कांट्रीब्यूशन ? वैस्ट बंगाल की सरकार खुद हड़तालें करवाती है। सी० पी० एम० की सरकार है यह कारखानों में हड़तालें करवाती है, प्रोडक्शन को रुकवाती है और फिर कहती है कि महंगाई बढ़ रही है। सरकार हड़ताल करवाए इस पर इसको शर्म आनी चाहिये। ऐसा करके सरकार में बैठकर ये अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की जो गैर जिम्मेदार सरकार है, मेरा वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि उसको डिसमिस किया जाए। लेकिन आप तो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। वहां आप पैसा थोड़ा देते हैं लेकिन इन लोगों को जो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, ज्यादा देते हैं। ये लोग एक पैसे भर का भी फायदा देश को नहीं दे सकते हैं, किसी तरीके से देश को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं कर सकते हैं उनको इस प्रकार ज्यादा पैसा क्यों देते हैं, क्यों आप इनकी आदत को खराब करते हैं। भारत सरकार जो पैसा देती जा रही है यह आगे चलकर उसको ही दुख देगा। 1985 में जो इनकी कारगुजारियां हैं ये जनता के सामने आ जाएंगी और मैं बताना चाहता हूं कि जनता आपको कभी बख्शने वाली नहीं है। 1985 में वह आपका तख्ता पलट देगी। उसके बाद कभी आपके वापिस पावर में आने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : आप तो आएंगे न ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : शास्त्री जी आपको क्या लेना देना है। आप तो कहीं भी नहीं है। आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको कहने की जरूरत है, उनको मैं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : प्राइस राइज के बारे में कहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उसी के बारे में कह रहा हूं। प्राइसिस को बढ़ाने में ये पार्टियां ज्यादा काम कर रही हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाती नहीं बल्कि उसको घटाती हैं। उसके बाद कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर बात है कि लोगों को तकलीफ होती है। इन्होंने जो गड़गड़ कर दी है उसको रोकने की व्यवस्था वित्त मंत्री जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एन० आर० ई० पी० में जितना पैसा आपने इनको दिया है क्या उसको इन्होंने खर्च किया है? क्या उन गरीबों में उस पैसे को बांटा है जिन लोगों के लिए आपने पैसा दिया है? उसका असर सारे देश पर पड़ेगा। बंगाल का असर सारे देश पर पड़ रहा है। दस करोड़ लोग कुछ कमाते नहीं और खाते ही हैं तो निश्चय ही इसका बुरा असर सारे देश पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता है। जो तब असर पड़ेगा उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं।

19.35 hrs.

[THE DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

बी० जे० पी० और लोकदल का गठबन्धन हो गया है। यह कैसा गठबन्धन है, एक इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी वजह से तो जनता पार्टी टूटी थी। आज फिर आपने गठबन्धन किया है। देश को बरबाद करने में ये लग गए हैं। इन पार्टियों पर कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है, ठीक तरह से इनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री महोदय खासतौर से ध्यान रखें कि यही लोग गड़बड़ कर रहे हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने ही गड़बड़ किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी जितनी निकम्मी है उतनी शायद ही कोई दूसरी पार्टी होगी। इस पार्टी ने इस देश का भट्ठा बैठा दिया। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जितने स्मगलर्स, होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स थे उन सबको 1975 में पकड़ा और उनके खिलाफ कार्यवाही की। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने आते ही उनको आजाद कर दिया और खुली छूट दे दी कि खूब लूटो। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। इसलिए यह सबसे निकम्मी पार्टी है और जिन सबने मिलकर जनता पार्टी बनायी थी, यह सब निकम्मी पार्टियां इस देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकतीं। जो हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता ने काम किया है उसी से देश का उत्पादन बढ़ सकता है, कीमतें कम हो सकती हैं और हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। यह लोग जो फिजूल की बात करते हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है, उलटी सीधी बातें करते हैं। कहीं हड़ताल करायेंगे, कहीं कुछ करा-एंगे, और रचनात्मक काम इनके पास कोई नहीं है इसी कारण से यह सारी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए आप वित्त मंत्री जी इनकी बातों की परवाह किए बगैर शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाइये। यही मुझे कहना है।

SHRI P.K. KODIYAN (Adoor) : This government came to power in 1980 with the promise that they would hold the price line. This promise has been grossly betrayed. There is one sentence in the statement made by the hon. Finance Minister which reads as follows :

> the government, as the House is aware, has been keeping a close watch on price movement from week to week and as was the case last year, this year also timely corrective measures have been taken".

Now the words 'close watch' appeared in every statement made by the Finance Minister in this House on the price situation. Every time he has been maintaining a close watch on the price situation ever since they came to power. What is the result ? Since I have no time, I will not refer to figures. Since 1980 there has been more than 34 per cent rise in the wholesale price and there has been an increase of more than 40 per cent in the consumer price index since January 1980.

The World Bank last May released a re-report on the Indian economy in which they complimented the Government of India for having contained inflation to a low level of

2.2 per cent.

Now, the hon. Finance Minister himself in the statement has admitted that on point to point basis the rate of inflation is now 6.9 per cent. And this year the Government has announced three instalments of dearness allowance which shows that the Government admits that there has been a continuous rise in the prices of essential commodities and thus the Government has failed to keep its election promise—the promise that they would hold the price line.

Now, a word about the public distribution system. So many Members have referred to the public distribution system and I think every member who referred to this public distribution system pointed out the utter inadequacy of the existing system. But I am pointing out another aspect of this public distribution system and that is, the Government's attitude towards the public distribution system. In Kerala we had worked out a fairly elaborate public distribution system under the Left Democratic Front Government led by the then Chief Minister Shri Nayanar and even the Government of India, that is the Union Finance Minister and other Ministers paid eompliments to the Kerala Government for having worked out such an effective public distribution system, within the limitations of a State Government. We were able to control the rising prices to a very large extent and essential commodities used to be distributed among the people through this elaborate network of the fair price shops.

Now, what has the Central Government done to this public distribution system ? The monthly requirement of an adult, is 320 gms. of rice and the total quantity required by Kerala comes to two lakh tonnes of rice per month. And the Central Government had never met this requirement in full. We got a maximum of one lakh 35,000 tonnes of rice per month. Since December, 1981 it was drastically reduced to 90,000 tonnes and we have been agitating. As a result of that, it has been increased to about one lakh and ten thousand tonnes now. But at the same time we find that the Central Government has prevented the State Government from entering the neighbouring States to get rice from other States. We have to depend merely on the supply from the Central pool and as a result of the failure of the Central Government to meet the requirements of rice for the working of the public distribution system the situation today is that it has been thoroughly disrupted and the price of rice has gone up in the open market up to Rs. 5.50 paise and in some places up to Rs. 6 per kg. Similarly, the prices of other articles which used to be supplied through this public distribution system also have gone up. So, this has been the attitude of the Central Government. A good public distribution system which has been working to the satisfaction of the common people of Kerala has been thoroughly spoiled and disrupted by the unhelpful attitude of the Central Government.

Apart from increasing the number of fair price shops the requirements of the States which are running the public distribution system have to be met by the Central Government in full.

Lastly, one more point, that is about rural areas. Most of the fair price shops are concentrated in the urban and mofussil areas. So far as the rural people are concerned, the public distribution system is running, practically on paper only.

So far as the weaker sections like Harijans, rural labour, agricultural workers, etc. are concerned, the public distribution system has not come to them at all. Therefore, I would request the Government to extend the public distribution system to the village areas and open up a large number of fair price shops and also see that essential commodities are distributed among the weaker sections at controlled prices. Then only the common man and the poorer sections can be saved from the effects of inflation and price rise.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have announced that the Minister will be called at 7.45. It is already 7.45. Three Members are yet to speak. If the House agrees, we can call the Minister at 8 o'clock.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I will

take only one point and that is the constant shrinkage of the public distribution system if not totally dismantling it.

The hon. Minister of Food claimed on 19th May this year that the public distribution system has been expanded and that the number of fair price shops as on 21 February, 1983 was 2,81,458 against 2,79,543 in February, 1982. So far as the increase in number is concerned, I agree that there has been expansion. But what about supply position to the shops ? According to his statement, in 1982 the total off-take from the public distribution system was 25.69 million tonnes, which comes to about 2.08 million tonnes per month. In 1983 when the number has increased, the figure available for the last three months of this year, comes on an average to 1.49 million tonnes per month. It will be further evident from the instructions given by the Government of India to the Delhi Administration saying that the ration quota which was 20 kg. per head per month should be reduced to 12 kg. per head per month. This is the actual situation which the House should know. I would only like to comment that every section of the House wants success of the public distribution system. But its success does not hinge on the arithmetical number, but it depends entirely on the physical availability of the foodgrains.

As a matter of fact, in almost all the States, including West Bengal, Kerala, Bihar, U.P. and so on, the total requirement of foodgrains necessary for the maintenance of the public distribution system has not been fully made available ; even what is partially promised is not physically made available. This physical possession is absolutely necessary. But my information is that the stock position of the Government of India in April was not more than 10 million tonnes for this year. I apprehend that whatever is available to the public distribution system now would not be available later and it would further shrink and the supply would be reduced.

You cannot make the public distribution system successful unless you have got physical control over the stock ; and to have physical control over the stock, nationalisation of the wholesale trade in foodgrains is absolutely necessary. That you cannot do and so the public distribution system cannot succeed. I hope at this late stage Government will reconsider this very basic question, on which depends the success of the public distribution system.

Three instalments of dearness allowance are due to the Central Government employees, which very much indicates the rise in the cost of living index. What is the position of the Government with regard to the release of these three instalments to the Government employees ?

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Sir, after the very eloquent speeches of Shri Ravindra Varma, Shrimati Pramila Dandavate and Shri Sunil Maitra, I will not take much time of the House. But I would like to emphasize certain points.

The prices are going up like flood water and it appears that the Government have lost total control over the rise in prices. Whenever the members belonging to the opposition say that the prices are going up, the leaders of the Government say that it is a global phenomenon and, therefore, it is difficult to control it here. Since they feel it is a global phenomenon, they do not try to do anything to control the rising prices.

While on the one hand the prices are rising, on the other hand, we notice that commodities are not available in the market, sometimes even in the fair price shops. For example, in the Nirman Bhavan fair price shop, from where we purchase many of our requirements, sugar and other items are not available.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Even sugar ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : Yes, sugar also. This shortage is reported sometimes in the newspapers also. So, the hon. Minister and the people in the Government must be aware of it. This rise in prices affects the Plan outlay and so many projects are being delayed. It is also clear from the Supplementary Demands for Grants

brought before the House by the hon. Minister.

In order to control the rising prices, the control on black money is very essential, but the Government are failing in that. Specially in the elections we are finding there is enormous use of black money, which causes inflation, which ultimately results in price rise.

MR. DEPUTY-SPEAKER : How is it that you alone know that ?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar) : The Garhwal elections.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Since Shri Dev has referred to the Garhwal elections, I may say that in that election the ruling party was pouring black money like anything ; so also in the Delhi election. This has caused a lot of inflation. Especially after the Delhi election, there has been rise in prices. After Delhi elections we had seen this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think all Parties have spent like this. Is it not so ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : Demonetisation of hundred rupee notes is a very basic factor in order to curb black money. But the Government may not do it. Deficit financing is also one of the reasons for price rise. All these points have already been placed before the hon. Minister. Therefore, I do not want to go into details regarding them.

So far as the consumer price index is concerned, according to Labour Bureau series Consumer Price Index for industrial workers, the base was 1960 when the price index was 100 ; in April 1983 it has gone up to 527, while in the month of March 1983, it was 519. It means there has been rise of 8 points in the price index. In May, the food crop index recorded an increase of 15 points mainly due to the rise in the prices of wheat, atta, dals, milks, onion, gur, tea, vegetables and fruits. Therefore, we are finding that there is always increase in the Consumer Price Index. (*Interruptions*). The Government is increasing the prices of all those commodities which are being essentially controlled by the Government itself, like diesel, fertilizer, insecticide, pesticide, and the rate of irrigation water and the rate of electricity and everything has been increased by the Government. The diesel price has been increased by the Government four times during the last three-and-a-half years. Fertilizer prices were also increased by the Government four times. At the same time insecticides and pesticides prices were also increased four times. Thus, we are observing that input prices in agriculture are always increasing but the farmers are not getting remunerative prices. The plight of the sugarcane growers is miserable. We know that. We have raised this a number of times in this House. They are not getting remuneratvie prices for the sugarcane and so the farmers are suffering.

Increase in the railway freights and fares also resulted in the price rise because when the transportation charge is increased, immediately it affects the prices. For example, I can say, per tonne load, per wagon per 100 kilometres, in respect of foodgrains the cost has gone up from Rs. 144.20 to Rs. 161.40. In respect of chemicals it has gone up from Rs. 163.30 to Rs. 183.40. In respect of salt it has gone up from Rs. 152.40 to Rs. 170.90. In respect of sugar it has gone up from Rs. 237 to Rs. 265. In respect of oil it has gone up from Rs. 276.10 to Rs. 309.90.

Thus we find that these freights are increased which ultimately resulted in the price rise also. Decrease in the number of fair price shops from 2,97,000 to 2,84,000 is very alarming and this Government appears to be a total failure in managing the economy of this country, and that is why our poor people are suffering.

I would like a categorical reply to all these points which I have raised.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिलकुल नाकाम हो चुका है। पिछले 35 सालों में···

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : जम्मू-काश्मीर में भी यही स्थिति है—क्या ?

20 hrs.

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं पूरे कन्ट्री के कांटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। पूरे मुल्क में यह हालत है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। प्रोडक्शन के जितने जराये हैं उन पर सरकार का कोई काबू नहीं है। ऊपर से तो सरकार कन्ट्रोल कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में मिल-ओनर्स पर सरकार का कोई काबू नहीं है, बल्कि एक तरफ से ब्लैक-मनी हमारी इकानमी को खाये जा रही है और दूसरी तरफ से स्मगलिंग हमारी इकानमी को तबाह कर रही है। कुछ लोगों के पास पैसा आ रहा है, चूंकि सप्लाई और डिमाण्ड की फिलास्फी के मुताबिक चीजें कम हैं और मांग ज्यादा है, लिहाजा जिनके पास चीजें हैं उनके पास ब्लैक-मनी आ रही है, चाहे वह करप्शन से आ रही हो या स्मगलिंग से आ रही हो।

चाहे वह किसी और जराये से आ रहा है, उन लोगों के हाथ में सारी की सारी प्रोडक्शन चली जाती है और जो आम आदमी हैं, जो फिक्स्ड इन्कम ग्रुप में आता है और जिसकी मेजोरिटी है चाहे वह सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वह गरीब दस्तकार हो और चाहे वह मजदूर-पेशा करने वाला हो, उसके लिए जीना दूभर हो जाता है और यह सिलसिला 25 सालों से चला आ रहा है और मैं तो इस हद तक कहूंगा आनरेबिल मिनिस्टर साहब को कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है—मैं खाली कांग्रेस (आई) की सरकार को ही इसके लिए दोष नहीं दे रहा हूं—कि जो मोनोपली बड़े-बड़े मिल-आनर्स की है, जहां पर एसेंशियल कामोडिटीज बन रही हैं चाहे वह दूध हो, चाहे साबुन हो और चाहे दूसरी एसेंशियल कामोडिटीज हों, उन पर जो इन लोगों का काबू है, वे ही हम सबको इलेक्शन के वक्त में पैसा देते हैं और हम उनके सहारे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। यह जो पालीटीकल पार्टीज का सिलसिला रहा है नेशनल लेबिल पर कि वे उनसे रकूमात ले लेती हैं, तो उसका खमियाजा जो चुकाना पड़ता है, वह गरीब आदमी को ही चुकाना पड़ता है। 35 वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है और इस बिना पर पर यह जंग लड़ी जा रही है। यहां पर तो जुबानी जंग तक ही महदूद है लेकिन हमें इसके खिलाफ जो जंग करनी होगी वह त्याग और तपस्या से करनी होगी और नेशनल कांटेक्स्ट में मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि इस जहर को आप निकाल दें और चाहे वह पार्लियामेंट का इलेक्शन हो और चाहे वह विधान सभा का इलेक्शन हो, करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है इस मुल्क में, ईमानदारी की बात यह है कि यह सारा पैसा उन्हीं बड़े मिल-ओनर्स से आ जाता है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता था।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार के लेबिल पर कौन सी जस्टिस लोगों को मिली है। जिन लोगों ने चोरी की और ब्लेक-मार्केटिंग करके काफी पैसा कमाया और करप्शन के जरिये से या लूट-खसोट करके जो भी पैसा कमाया, क्या हकीकत यह नहीं है कि सरकार ने उनको कन्सेशन दिए और फिक्स्ड डिपोजिट करने के लिए उनको दावत दी और यह कहा कि जितना करोड़ों रुपया उनके पास है, वे बैंकों में जमा कराएं और हम उनको कन्सेशन देंगे। इस तरीके से जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो ब्लैक-मार्केटिंग से पैसा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा पैसा व्हाइट करने के लिए साधन पैदा किया गया। इसलिए मैं आपकी इजाजत से आनरेबिल मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब स्टेट्स का हो रहा है, जो सेन्टर से बहुत दूर हैं और जो बहुत ही बैकवर्ड हैं और जिनकी अपनी मुश्किलात हैं, अपनी परेशानियां हैं। मैं आपको जम्मू व काश्मीर स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं। हमने यह कोशिश की थी कि हम अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हम 20 करोड़ रुपये की सब्सीडी अनाज के लिए देते थे और उससे गरीब लोगों को बहुत फायदा पहुंचा था। हम सेन्टर की इमदाद पर निर्भर हैं और हम जो 20 करोड़ रुपये की सब्सीडी राशन के लिए देते थे, जब उस स्कीम को खत्म किया तो 3 रुपये का 6 सेर जो चावल आता था, वह आज 15 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। यानी हमने जो

सेक्रीफाइस की है, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि चाहे वह जम्मू व काश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो और चाहे नेफा हो, जो फार-फ्लंग एरियाज हैं, उन इलाकों में फ्रेट की एक बहुत बड़ी प्राब्लम है और वह सामान के दाम डबल कर देती है। दिल्ली के आसपास जहां पर रेलवे का सिस्टम है और रेलों का जाल सा बिछा हुआ है और जो इलाके ऐसे हैं वहां पर यह हालत है, तो वे इलाके जो सड़कों के जरिये **रेस्ट आफ दि कन्ट्री** से कनेक्टेड हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू व काश्मीर है और लद्दाख जैसे इलाके हैं, उनका क्या हाल होगा। आज हालत यह है कि वहां पर यहां के मुकाबले में दुगने भाव पर चीजें मिल रही हैं क्योंकि वहां पर माल को ले जाने में बहुत ज्यादा फ्रेट लगता है। इसलिए ऐसी स्टेट्स को जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं और जहाँ पहले से ही गिरानी है पूरे मुल्क के कान्टेक्स्ट में, वह और भी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्टेट्स की खासतौर पर मदद की जाए। लद्दाख में एक माचिस की डिबिया 8 आने आने या 60 पैसे से कम में नहीं मिलती है और दूसरी चीजें भी बहुत महंगी हैं, तो क्या सेन्टर का यह फर्ज नहीं है कि इस महान् देश में जहां पर ऐसे पाकेट्स हैं, जहाँ बहुत ज्यादा गिरानी है और कमरतोड़ महंगाई है, उनकी वह मदद करे। जब दिल्ली वालों को इस महंगाई की शिकायत हो सकती है, लखनऊ वालों को हो सकती है और जयपुर वालों को हो सकती है, जहाँ पर सारी शक्ति, सारी ताकत महदद है, सारे साधन मौजूद हैं, तो उन रियासतों के बारे में आप क्यों नहीं सोचते, जहां पर इनके मुकाबले में और भी ज्यादा गिरानी है। इसलिए इसके लिए आपको कोई उपाय ढूंढने पड़ेंगे और यह सेन्टर का फर्ज है, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का फर्ज है और सरकार का फर्ज है कि वह उनको कमपेन्सेट करे और इस महंगाई को रोके। कम से कम हमें उस लेबिल पर तो रहने दीजिए गिरानी के मामले में, जो रेस्ट **आफ दि कन्ट्री** में है। हमें फ्रेट के कारण डबल जो देना पड़ता है, उससे हमारे यहाँ की एकोनामी तबाह हो रही है।

मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं जम्मू और काश्मीर की मिसाल देना चाहता हूं। जम्मू व काश्मीर की एकोनामी टूरिज्म पर मुन्हसिर है।

इस साल हमारा टूरिज्म बिल्कुल फेल्योर रहा है। टूरिज्म न होने की वजह से जो हमारे यहां हेण्डीक्राफ्ट्स पर पलने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रोड्युस को मार्किट नहीं मिल रही है। इस तरह से हमारे यहाँ हजारों दस्तकार लोग बेकार पड़े हुए हैं। इसी तरह से हमारे यहां हाउस बोट्स हैं, होटल हैं। हमने उनके रेट्स 25 परसेंट कम कर दिए हैं लेकिन फिर भी विजिटर्ज के न आने की वजह से वे खाली पड़े हुए हैं। इससे हमारी इकोनोमी पर स्ट्रेस है। क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता कि जो ऐसी स्टेट्स हैं, उनकी तरफ तब्बजो दें जिनकी इकोनोमी पर ज्योग्रोफी के मुताबिक स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Conclude now. You are making so many demands which he cannot reply.

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हमारे यहां 80 परसेंट लोग देहातों में रहते हैं। वे बिचारे कभी फ्लड आने पर और कभी ड्राट पड़ने से तबाह हो जाते हैं। वे कुछ पैदावार नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ऐसी पालिसी क्यों नहीं बनाती है कि उनकी फसल इन्श्योर हो सके और जब भी ऐसी क्लमिटी आ जाए तो इन्श्योरेन्स से उनकी भरपाई हो जाए ?

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ڈسٹری بیوشن سسٹم بالکل ناکام ہو چکا ہے پچھلے ۳۵ سالوں میں۔

شری رام سنگھ یادو (الور) : جموں کشمیر میں بھی یہی استھتی ہے کیا۔

شری عبدالرشید کابلی : میں پورے کنٹری کے کانگرس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ پورے ملک میں یہ حالت ہے کہ آپ کا ڈسٹری بیوشن سسٹم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے۔ پروڈکشن کے جتنے ذرائع ہیں ان پر سرکار کا کوئی قابو نہیں ہے۔ اوپر سے تو سرکار کنٹرول کر رہی

کرپشن کے ذریعہ سے یا لوٹ کھسوٹ کر کے جو بھی پیسہ کمایا گیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ سرکار نے ان کو کنسیشن دیا اور فکسڈ ڈپوزٹ کرنے کے لیے ان کو دعوت دی اور یہ کہنا کہ جتنا کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہے وہ بینکوں میں جمع کرائیں اور ہم ان کو کنسیشن دیں گے۔ اس طریقے سے جو چوری کرنے والے لوگ ہیں جو بلیک مارکیٹنگ سے پیسہ اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں ان کو پیسہ وہائٹ کرنے کے لیے سادھن پیدا کیا گیا۔ اس لیے میں آپ کی اجازت سے آنریبل منسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان ان غریب اسٹیٹس کا ہو رہا ہے جو سینٹر سے بہت دور ہیں اور جو بہت ہی بیک ورڈ ہیں اور جن کی اپنی مشکلات ہیں اپنی پریشانیاں ہیں۔ میں آپ کو جموں و کشمیر اسٹیٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں: ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہم ۲۰ کروڑ روپے کی سبسڈی اناج کے لیے دیتے تھے اور اس سے غریب لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔

ہم سینٹر کی امداد پر نر بھر ہیں اور ہم جو ۲۰ کروڑ روپے کی سبسڈی راشن کے لیے دیتے تھے جب اس اسکیم کو ختم کیا تو تین روپے کا چھ سیر جو چاول آتا تھا وہ آج ۱۵ روپے میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ یعنی ہم نے جو سیکری فائس کی ہے اس کی قیمت ہمیں چکانی پڑ رہی ہے۔ اس لیے میں منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ چاہے وہ جموں و کشمیر ہو چاہے ہماچل پردیش ہو اور چاہے نیفا ہو جو فارفلنگ ایریاز ہیں۔ ان علاقوں میں فریٹ کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور وہ سامان کے دام ڈبل کر دیتی ہیں۔ دلی کے آس پاس جہاں ——— پر ریلوے کا سسٹم ہے اور ریلوں کا جال سا بچھا ہوا ہے اور جو علاقے ایسے ہیں وہاں پر یہ حالت ہے تو وہ علاقے جو سڑکوں کے ذریعہ "ریسٹ آف دی کنٹری" سے کنیکٹڈ ہیں جیسے کہ ہماچل پردیش ہے جموں و کشمیر ہے اور لداخ جیسے علاقے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ آج حالت یہ ہے کہ وہاں پر یہاں کے مقابلے میں دگنے بھاؤ پر چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ وہاں پر مال کو لے جانے میں بہت زیادہ فریٹ لگتا ہے۔ اس لیے ایسی اسٹیٹس کو جو بیک ورڈ اسٹیٹس ہیں اور جہاں پہلے سے ہی گرانی ہے پورے ملک کے کانٹکس میں وہ اور بھی زیادہ ہو سہے لیکن پروڈکشن کے معاملے میں مل اونرس پر سرکار کا کوئی قابو نہیں ہے بلکہ ایک طرف سے بلیک منی ہماری اکانومی کو کھائے جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اسمگلنگ ہماری اکانومی کو تباہ کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے چونکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی فلاسفی کے مطابق چیزیں کم ہیں اور مانگ زیادہ ہے۔ لہذا جن کے پاس چیزیں ہیں ان کے پاس بلیک منی آ رہی ہے چاہے وہ کرپشن سے آ رہی ہو یا اسمگلنگ سے آ رہی ہو۔ چاہے وہ کسی اور ذرائع سے آ رہا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ساری کی ساری پروڈکشن چلی جاتی ہے اور جو عام آدمی ہیں جو فکسڈ انکم گروپ میں آتا ہے اور جس کی مجبوری ہے چاہے وہ سرکاری ملازم ہو چاہے وہ غریب زمیندار ہو اور چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہو اس کے لیے جینا دوبھر ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ ۳۵ سالوں سے چلا آ رہا ہے اور میں تو اس حد تک کہوں گا آنریبل منسٹر صاحب کو کہ ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے میں خالی کانگریس (آئی) کی سرکار کو ہی اس کے لیے دوش نہیں دے رہا ہوں کہ جو مونوپلی بڑے سے بڑے مل اونرس کی ہے جہاں پر ایسینشیل کموڈیٹیز بن رہی ہیں چاہے وہ دوندھ ہو چاہے صابن ہو اور چاہے دوسری ایسینشیل کموڈیٹیز ہوں ان پر جو ان لوگوں کا قابو ہے وہ ہی ہم سب کو الیکشن کے وقت میں پیسہ دیتے ہیں اور ہم ان کے سہارے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ جو پالیٹیکل پارٹیز کا سلسلہ رہا ہے نیشنل لیول پر کہ وہ ان سے رقومات لے لیتی ہیں تو اسکا خمیازہ جو چکانا پڑتا ہے وہ غریب آدمی کو ہی چکانا پڑتا ہے۔

۳۵ ورشوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس بنا پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہاں پر تو زبانی جنگ تک ہی محدود ہے لیکن ہمیں اس کے خلاف جو جنگ کرنی ہوگی وہ تیاگ اور تپسیہ سے کرنی ہوگی اور نیشنل کانٹیکسٹ میں میں اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس زہر کو آپ نکال دیں اور چاہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو اور چاہے وہ ودھان سبھا کا الیکشن ہو کروڑوں روپے جو خرچ ہو رہا ہے اس ملک میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ انھیں بڑے مل اونرس سے آ جاتا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا۔

دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے لیول پر کونسی جسٹس لوگوں کو ملی ہے۔ جن لوگوں سے چوری کی اور بلیک مارکیٹنگ کر کے کافی پیسہ کمایا اور

جاتی ہے تو ایسی اسٹیٹس کی خاص طور پر مدد کی جائے لداخ میں ایک ماچس کی ڈبیہ آٹھ آنے یا ۶۰ پیسے سے کم میں نہیں ملتی ہے اور دوسری چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں تو کیا سینٹر کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس مہان دیش میں جہاں پر ایسے پاکٹس ہیں جہاں بہت زیادہ گرانی ہے اور کمر توڑ مہنگائی ہے ان کی وہ مدد کریں۔ جب دلی والوں کو اس مہنگائی کی شکایت ہو سکتی ہے لکھنؤ والوں کو ہو سکتی۔ اور جے پور والوں کو ہو سکتی ہے جہاں پر ساری سنگنی ساری طاقت محدود ہے سارے سادھن موجود ہیں تو ان ریاستوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے جہاں پر ان کے مقابلے میں اور بھی زیادہ گرانی ہے۔ اس لیے اس کے لیے آپ کو کوئی اپائے ڈھونڈنے پڑیں گے اور یہ سنٹر کا فرض ہے فائننس منسٹر صاحب کا فرض ہے اور سرکار کا فرض ہے کہ وہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور اس مہنگائی کو روکیں۔ کم سے کم ہمیں اس لیول پر تو رہنے دیجئے گرانی کے معاملے میں جو "ریسٹ آف دی کنٹری" میں ہے۔ ہمیں فریٹ کے کارن ڈبل جو دینا پڑتا ہے اس سے ہمارے یہاں کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے۔

میں دو منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ میں جموں کشمیر کی مثال دینا چاہتا ہوں جموں و کشمیر کی اکانومی ٹورزم پر منحصر ہے۔ اس سال ہمارا ٹورزم بالکل فیلیور رہا ہے۔ ٹورزم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے یہاں ہینڈی کرافٹس پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی پروڈیوس کو مارکیٹ نہیں مل رہی ہے۔ اس طرح سے ہمارے یہاں ہزاروں دستکار لوگ بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے یہاں ہاؤس بوٹس ہیں ہوٹل ہیں۔ ہم نے ان کے ریٹس ۲۵ پرسینٹ کم کر دیئے ہیں لیکن پھر بھی ٹورسٹس کے نہ آنے کی وجہ سے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری اکانومی پر اسٹریس ہے۔ کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو ایسی اسٹیٹس ہیں ان کی طرف توجہ دیں جنکی اکانومی پر جغرافی کے مطابق اسٹریس اور اسٹرین پڑتا ہے۔

MR. DEPUTY-SPEAKER : Conclude now. You are making so many demands which he cannot reply.

شری عبدالرشید کابلی : ہمارے یہاں ۸۰ پرسینٹ لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ وہ بے چارے کبھی فلڈ آنے پر اور کبھی ڈراٹ پڑنے سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ پیداوار نہیں کر پاتے۔ گورنمنٹ ایسی پالیسی کیوں نہیں بناتی ہے کہ ان کی فصل انشور ہو سکے اور جب بھی ایسی کلامٹی آ جائے تو انشورنس سے ان کی بھرپائی ہو جائے۔

SHRI SATISH AGARWAL : You are very kind to him. Probably, for Mr. Kabuli, this is the first speech in this House and last speech in this House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why do you say so ?

SHRI SATISH AGARWAL : God knows whether we will meet again in the next Session or not.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : He said, "God knows." No, only Mrs. Gandhi knows.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Perhaps, you know a little bit.

First of all, I express my gratitude to all those hon. Members who have made their contributions in the debate and I am particularly thankful to Mrs. Pramila Dandavate who initiated the discussion. I would frankly admit that perhaps in this matter, she represented all the wives including the wives of the Minister. The only difference for us is that we have not reached this stage when the wives of the Ministers of the present Government are not to organise a demonstration against us as Mrs. Dandavate had to do while Prof. Madhu Dandavate was the Minister. This is the only little difference.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Because, I am with the people.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : No. Because, we have been able to maintain the situation within a manageable limit and that is the difference between the situation which prevailed at your time and the situation prevailing now.

PROF. MADHU DANDAVATE : We have more civil liberties in our family.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You have been able to suppress your wives very successfully.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I do not know who suppresses whom in these days.

I would not like to go to the statistics because these are known to the hon. Members. It is never my contention that the situation is quite happy and I myself admitted in the text of my statement and not only in this statement but throughout I have maintained that this is an area where there is no room for complacency. Because, we have to keep in mind that the Indian economy is basically not only marginal but it is very sensitive with little changes here and there and there can be a big difference in the actual state of affairs.

I have enumerated in my statement the strategy which we are pursuing to tackle the problem. We are tackling it both from supply side and from demand side. From supply side, as I have indicated in my statement, we do it by importing certain essential commodities where there is a gap between the demand and availability, by improving the public distribution system, by stepping up the release of certain essential commodities through the public distribution system itself and, at the same time, by providing incentives for higher production.

In this connection, one point has been made and a number of hon. Members have made their contribution to say that the public distribution system is collapsing in this country. They have even gone to the extent of saying that the supply through the public distribution system has gone down. I do not know from where they have got the figure. Particularly, I was listening very carefully to Mr. Chitta Basu when he mentioned about the figure during the three months of the current calendar year. I do not know which months, whether it is July, June and May or first three months of January, February and March. But whatever it may be, I have got the figure and this figure can be checked up and verified. In the first five months of the current calendar year, January to May, the stocks distributed through the public distribution system was 7.53 tonnes as against 5.93 tonnes in the same period of 1982 and 5.0 million tonnes in 1981. Therefore, in absolute terms, it is not decreasing, but it is increasing. In June, 1983, the offtake was 1.29 million tonnes as against 1.16 million tonnes. Therefore, if you take the block of first five months as a whole, even the block of first six months, including June, for which I have given the figure...

SHRI CHITTA BASU : If you do not mind my interruption, I may point out that I have given the figure that Mr. Bhagwat Jha Azad claimed that in 1982, the total offtake was 25 million tonnes and then I worked that out.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : What you have done, as I understand you, is this. The Food Minister has given an average figure for the whole year and what you have done is that you have just taken the first three months or two months and you have forgotten that the offtake increases much more from the beginning of the festive seasons and all the festive seasons from Onam to Diwali and Holy are yet to come. Therefore if you take into account the total average figure, that is different. I have give you my figures. These are not secret figures. These can be checked and verified. I am not disputing that figure. But I do not know whether you have quoted from the text of his speech or from the newspaper report or from the Question in Parliament...

SHRI CHITTA BASU : From the newspaper report ; it was reported in the Advisory Council meeting.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Then you say that you are quoting from the newspaper report. I am quoting the figures which have been given to me by my people. You said that you were quoting from the newspaper as reported to be the observations of the Food Minister.

SHRI CHITTA BASU :...in a meeting of the Advisory Council for the Public Distri-

bution system.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Whatever it may be. The point is that from this figure, we find that it has not in absolute terms decreased. The same is the case with the number of fair price shops. The fair price shops in some States have decreased in number because there was some reorganisation, particularly, in U.P. That is why there was shrinkage in a particular area ; it was because of certain reorganisation that took place. But if you look into the figure of offtake, even in U.P., as a result of the reduction in the number of fair price shops, the net offtake did not decrease ; the net offtake increased and it is bound to increase.

It is not my case that we have been able to cover the entire country through public distribution system. Even notionally, if I assume, that 2.88 lakhs is the number of fair price shops which we have, all of them are effective, but after all, the number of villages in this country is more than 600,000. Therefore, 2,84,000 is not to cover the entire area. Not to speak of that distribution system itself, its strength and effectiveness varies from State to State. We know in certain States, the distribution system is quite satisfactory. But, in many States, the distribution system and distribution outlay are not so satisfactory. But this is one of the instruments. Quite a number of Members have made their observations that by improving the distribution system, we will be able to check the prices. No. We will be able to insulate the people from the effect of the price rise. Strengthening the distribution system itself, is possible. In order to reduce the impact of the price rise on the vulnerable sections of the community, if we can strengthen the public distribution system, to that extent, we will be able to help them.

One Hon. Member claimed—I would not have referred to him if he would not have stated that my statement is a ** —that I should not compare the 11 weeks of Janata period from 11th May to 20th July but I should compare when we assumed office. That is why I am comparing when we assumed office. When we assumed office on 14th January, 1980, the annual rate of inflation was 21%, in the wholesale price index.

After one year in 1980-81, it came down to 16.7%. In 1981-82, it came down to 2.4%. In 1982-83, it increased to 6.2%.

The annual quota of inflation based on the consumer price index also came down, 12.3%, 12.6%, 8.8% and 9.8%.

If we would have maintained the rate of inflation which we have inherited, then today the situation would have been, 21% during 1980-81 on the top of 21% in 1979-80 ; 21% during 1981-82 on the top of 21% in 1980-81 and 21% during 1982-83, and that rate would have remained static. Therefore, let us not be assertive to say a statement is a white lie.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Please don't say Janata rule in 1979. There was no Government in 1979.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : That is the time when we inherited it.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : You installed the Government. We have no Government at all during 1979.

SHRI SATISH AGARWAL : Please be very fair. In percentage you win. In percentages, we lose. That is true. 21%, 16%, 6%, and 7%. Of course, you win percentage-wise. But point-wise, from March, 1977 up to July, 1979 when Janata was in power, price rise has been 26 points, in 26 months one point per month. But during these 42 months, the price rise has been 90 points, that is 2 points per month.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I have taken your point. But definitely I should not remind the former Revenue Minister what has been the impact of the Budget by Mr. Choudhary Charan Singh when he was Deputy Prime Minister and Finance Minister of the Janata Party Government starting from the day of presentation of the Budget.

SHRI SATISH AGARWAL : Please

**Expunged as ordered by the Chair.

don't compare the figures when Mr. Charan Singh was the Prime Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I am just saying.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Please do not take 1979.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I am telling you that I have taken 1979-80 from May to July. Your contention is that I have taken the period May to July and so, why not earlier period.

I have taken from May to July because every year in this period there is a rising trend in price. If you take into account the seasonal factors, you will not find a single year when the prices have not risen in the period from May to July. That is the relevance. The relevance is not that it is giving me certain statistical satisfaction because I myself have admitted that the annual rate of inflation has gone up, it is 6.9 per cent as compared to 6.2 per cent in 1982-83. I myself have admitted. But this period is relevant because every year you will find that from May to July there is an upward trend. The seasonal factors are there. The vegetable prices go up, the milk prices go up, the cereal prices go up, the prices of sweetening agents go up, the edible oil prices go up. What are the commodities which have contributed the maximum to rise in prices ? These are the commodities.

Mr. Ravindra Varma has quoted some figures. It is very difficult to reply to the points made by Mr. Ravindra Varma, particularly for me, because whenever he makes his observations, his brilliant speech always takes me and I forget to note down the points. But somehow I noted this particular point. He has quoted some figures and has tried to show how exorbitant is the price rise. My contention is that it is a selective approach. If you quote certain figures to show that prices have gone up in the retail—I am talking of retail prices—I can also quote certain figures where the prices have gone down. For instance, grams minus 8.1 per cent ; mashoor dal minus 12 ; mustard oil, the increase is plus 1.3 ; sugar minus 12.7... (*Interruptions*) Retail price. The number of centres, so far as sugar is concerned, is nine. Mustard oil twelve centres...

AN HON. MEMBER : Who gave the figures ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : From 12 centres they have collected the figures.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Thirteen centres. (*Interruptions*) These are standard centres from where we collect the figures and from where you are quoting statistics. You have already quoted the same figure. How are you demanding D.A. ? Based on the same basket of commodities, on the same statistical yardstick. The figure which Mr. Ravindra Varma quoted is from the same centres and from the same indicators.

PROF. MADHU DANDAVATE : About sugar, is there any compositor's mistake, printer's mistake ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I do not think so. You know the position of sugar. We need not tell you. (*Interruptions*) In that way we would not be able to finish. Let us go ahead.

Mr. Maya Thevar went to the extent of asking why the growers are not getting the prices. Can you tell me in which year the area of the cane-growers was only 15 per cent during this period of the year ? Can you show me one year ? You are just making long claims. Is it not a fact that the sugarcane growers, in 1978-79, had to burn their sugarcane ? If we had not increased the sugarcane price from Rs. 8 to Rs. 21 per quintal and if we had not ensured that the growers would get their price, there could not have been any production. That is a fact. That is the difference between good management and bad management. Today you are coming forward with tall claims, 'No ; the entire economy is in doldrums'. What is in the doldrums ? You are talking of planning. Can you show me a single Plan period ? Take the case of power generation. You were very much critical of it.

What was the situation when we started the plan for the periods from 1947-1979 ? This country created, in the power sector, an installed capacity of 28,000 M.W. And, in one period, we are adding 14,000 M.W.—a meagre achievement ! Take the case of Petro-

leum products. Can you say that our economy was in the doldrum as you are claiming ? When we inherited and when we started the current planning in 1979, the total oil production was 10 million tonnes. We are going to end with 26 million tonnes in 1983-84. If we end the current plan with 30 million tonnes, will you say that the economy is in doldrum ? You said that the target of coal production is 165 million tonnes. Even if we can reach fifty per cent of it, that is, 80 to 85 million tonnes, we should feel happy. It should not be forgotten that we had already reached 137 million tonnes in 1982-83. I admit, however, that there would be a certain slippage. It is bound to take place. If I am to give priority in certain sectors like power generation, like creating irrigation potentiality, like petroleum products—I am not here talking in financial terms—definitely Rs. 97,500 crores would become much more. Even in physical terms, according to mid-term appraisal, if we look at the production of cement, fertilisers or aluminum, we are reaching the target. The target which we have fixed is in physical terms. At the same time, we have admitted that there will be certain areas, where there may be a shortfall. Can you tell me that it is due to bad management of our economy ? Shri Samar Mukherjee is present here. He will bear me out that in 1942-43 Bengal famine took place due to the impacts of drought. In those days, we used to call it as seer—not kg. One seer of rice was costing us Re. 1. More than five million people died. The people did not have the purchasing power to purchase one seer of rice. As a result of famine more than 5 million people died. It was an unprecedented drought. The Marxist Government in West Begal cannot deny this unprecedented drought in West Bengal. There was a shortfall of foodgrains production due to severe drought last year. It had been possible for us to contain it. It is not because of some miracle but it was because of certain proper policies and programmes undertaken by us. It was because of the fact that 300 to 400 million man days of additional employment are created annually in the rural areas. It was because of the fact that more than 42 lakhs families were brought within the purview of IRDP programme by spending Rs. 900 to 1300 crores. This is the kind of management of our economy. It is very easy to say that the whole economy is in doldrums. Why is it in doldrum ? From the balance of payment position is it in doldrum ? Is it in doldrums because of it ? Upto 1978, the total growth of the economy was 3.5%. Even in the first three years of the Plan, we had achieved a five per cent growth. Does this indicate that the economy is in the doldrum ? Is the economy very badly managed or poorly managed ? Shri Maitra, our good old friend—Shri Sunil Babu—has made a very interesting comment that there is a total economic crisis. He has quoted the consumer price index by saying that in 1974 it reached a record figure and has come to the conclusion from there that there is an economic crisis. And, emergency in 1975 was the outcome of the economic crisis. He has conveniently forgotten that in 1974 it is true that we had a price rise—the annual rate rose up to 30% in September and even the consumer price index in 1974-75 had reached 321, highest at that point of time. But if he takes the trouble of going through the Economic Survey he will find out that it came down to 286 in the next year and that is the only one year in that whole decade that it came down.

AN HON. MEMBER : That was emergency time ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Therefore, the economic crisis did not deepen. The situation improved. You will have also to keep in mind that from negative figure next year we had plus figure in our trade account. Therefore, he need not worry about the collapse of the economy. If we could have survived...

AN HON. MEMBER : With hunger.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : In certain times there are crisis and this is for us to react in a particular way. Again I am referring to Shri Ravindra Varma. He said that it is a turbulent sea and how to pilot the ship in the turbulent sea. I can assure you that you can have the confidence in the pilot and the pilot surely is not merely the Finance Minister of the country but pilots of Indian economy are the farmers who are working in the fields, the workers who are

working in the factories and they have responded. They are not as pessimist as you are. They have responded and they have responded in a befitting manner.

Another pertinent point has been made about black money. I agree with you that this is an area where we shall have to be firm. But who are talking of it ! May I respectfully remind Mr. Ravindra Varma just to remember the speech made by his cabinet colleague, the then Finance Minister that why the number of raids, searches and seizures against the smugglers and foreign exchange racketeers are getting reduced. Is it not a fact that you were bold enough to say that these all exercises done by the previous Government were politically motivated. Who gave the respectability to the smugglers and foreign exchange racketeers by equating them with political detenus. Please look at the figure of number of income tax raids, customs raids and enforcement raids, and the amount of smuggled goods seized. I am giving the figure of the last four months. It was reached the figure of 1300. Surely, my colleague, Mr. Satish Agarwal, who has the experience of the Revenue Department will agree with me that the number of raids is reasonably encouraging. We have stepped up that action. COFEPOSA detentions we have stepped up. Even for dealing with the hoarders and profiteers you yourself brought one ordinance. The ordinance could not be converted into law because of dissolution of Lok Sabha but when I as the Commerce Minister piloted that Bill—ordinance to be converted into Bill to tackle the hoarders and blackmarketeers—you opposed yourself that ordinance. This is the situation. A situation has been created where we cannot make a distinction between one type of offenders and economic offenders.

SHRI SATISH AGARWAL : We opposed ourselves in 1979 that is why we went away.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : It is not that excuse that action should not be taken or we should not act firmly but what I am saying is this is the area where if I want to detain one person under COFEPOSA I cannot get the approval of the Home Minister of that State.

Each and every case is to be brought to Delhi. Detention order is to be passed by my officer ; then it will be complied with. And when you are tackling these types of economic offenders who are vere powerful, who are the kingpins, it is not an easy thing to tackle them. I have instructed that even in respect of those who are released, let them be put behind bar for one month, which is the pepiod for which we can keep. You must put a fear in the minds of all these smugglers, racketeers and profiteers. Sir, I really feel for Mr Wanchoo. He made certain recommendations and observations ; I do not know whether he is still living. But if he would have listened to the debate of this House, he would have been really surprised how the figures quoted by him varied from Rs. 1300 crores to Rs. 40,000 and 50,000 crores. So, why are you indulging in this type of pure guess work ? The Wanchoo Commission Report is available. You know the figure which he quoted, which he indicated. So, everything cannot be passed on, in the name of Wanchoo Committee Report. I am not trying to venture and say what is the quantum. It is not very important to quantify the black money ; what is important is to tackle, and to know how effectively to tackle it. We have made various efforts including certain schemes with which you did not agree. I do not say you had no reason to oppose that. You opposed it. You had reasons to oppose it. But definitely there are no two opinions that if we have to tackle these problems we have to deal effectively with them. You may say what we are doing is not enough. But to say that nothing is being done and everything is done in collusion would be a thing which is totally untenable, unacceptable and far from the truth.

Then, one more point was raised. I was asked : Why are you not reducing your non-plan expenditure, non-development expenditure ? I can do it. But, would you help me in doing so ? 73 percent of our non-plan expenditure are accounted by Defence, by Subsidies, and there is a third one which I am just forgetting, I will just tell you...

SHRI SATYASADHAN CHAKRA-

BORTY : Interest payments.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Yes, interest payments. These are : Interest payments, Defence and Subsidy. Interest payments you have to do. That is your obligation and that is one of the major source of your finance. The third area is consumption expenditure ; I mean, the expenditure on the Defence services, Economic Services, General Services, and other Services. Here also we are making serious efforts.

SHRI SATISH AGARWAL : But there is still a scope.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I agree there is a scope and I am telling you to what extent I am trying to do it. If you look at the absolute figure—it is not in terms of percentage, in terms of percentage it is decreasing,—you will find this ; I am giving the absolute figure. In 1981-82 it increased by 17.8% over 1980-81. In 1982-83 Revised Estimate it increased by 15.7% over 1981-82. In 1983-84 Budget Estimates the increase is 13.1%. Therefore, we are trying to reduce it. But we shall have to keep one thing in mind. Almost every third day I am being asked : "What are you going to do about 11 lakhs of pensioners ?" Letters are there : questions are there. For the first time in the history of the country, we appointed the Pay Commission, but we could not wait for the interim report of the Pay Commission ; the Pay Commission was appointed and simultaneously the interim relief is announced. And in terms of money it is Rs. 253 crores. What I am talking is a rough calculation and it will be a little more. There are deficits of States. And if I tell this thing, Mr. Sunil Maitra and his friends will simply jump on me. In 1981-82 the States' Deficits were of the order of Rs. 1127 crores. In 1982-83 it was Rs. 694 crores excluding Rs. 1743 crores which I have converted into Medium-term Loans. Therefore, these are areas where it is not very easy to do it.

I do not say that there is not a case. We shall have to do something. We shall have to try. But you have to understand the enormity of the problem and keeping that in view whatever best is possible, we are trying to do. It is nobody's case that we have been able to reduce the price. Who has said ? What we have said is that we shall try to keep it within the manageable limit and we have kept it within the manageable limit. We have not allowed it to reach two digits and I do say that it would be possible with the cooperation of all the sections in the House and with the cooperation of our workers in the factories and the farmers in the field. It will be possible to maintain it. That we are doing. In the case of agriculture, we have increased. Each year, we have increased the price of agricultural commodities. Today you are talking of the kisans. What was the price they used to give for wheat in 1978-79 ? Even if you give the allowance of inflation... (*Interruptions*)

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Price of inputs should be less.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I am coming to that. You will agree with me that the moment you find that it is going to have an adverse effect on the fertiliser consumption, we ourselves reduced it. You cannot have both the ends together. On the one hand, you will suggest to me to reduce the price of the inputs and on the other hand you will say what is the best instrument through which you can make it effective. So far as the fertiliser is concerned, the only instrument through which you make it effective is by subsidy. I have done it by giving 7.5% reduction which is causing how to increase the subsidy of more than Rs. 250 crores, on the top of Rs. 700 or Rs. 800 crores worth of fertiliser subsidy already given. Therefore, these are the factors which we have to take into account and we have to keep these factors in view. On the top of it, my trade union friends should not mind it. They have the type of concept of collective bargain and the pressure they are putting on me and who have become almost whipping boy, still we have to increase it by 14%. We have already increased it recently in the engineering agreement which the West Bengal Government has entered into including the public sectors in that region. There, we have agree to 1.5 which they have also agreed. Therefore, these are the issues,

these are causing and these are putting tremendous stress and burden on our economy. Somebody advised me to look at ten years back. What was the price ? What was the situation ten years back ? It is true that ten years back the price was less. But ten years back, the gross national income was 35,000 crores of rupees. Today it is Rs. 130,000 crores. Therefore, if you take the current price, you will have to calculate the price also at the current price level, inflation also at the current price level and income also at the current price level. You cannot have both the ends together.

The last point which I would like to mention is about the demand side.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : What about the DA instalments to the Government employees ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Don't ask me that commitment. Mr. Varma wanted to know the actual position as to why this money supply has increased and what was the rationale for changing this year now so quickly. Therefore, from 7 we have increased the CRR to 7.5 and then to 8.0. Now, from 27th August, we are to give 8.5. The aggregate deposits have increased in this period substantially and one of the reasons may be of the remittance, which is about Rs. 100 crores, as referred to by Mr. Maitra. That is relevant after the presentation of the Budget. If that trend continues, naturally the aggregate deposits will be increasing and in order to mop up the excess liquidity we shall have to adjust this year. So far as the credit to the Government is concerned and the gross commercial credit is concerned, you know the bulk is for credit for food procurement. The exact figure I do not have now, may be around Rs. 800 crores upto end of July. This year, apart from the food credit, non-food bank credit has also increased. Last year the figure was negative. But in the first three-four months of the current financial year it has increased substantially.

I do agree with one suggestion, a very positive suggestion made by the initiator of the discussion, Shrimati Dandavate, and many other hon. Members have also supported it. And that is, side by side we have to build up a strong consumer movement. We should build up a strong consumer movement ; it is not an agitational movement, it is constructive and educative. If we can build up a strong consumer movement and create consumer awareness, that would also contribute, not to check the price, but to insulate the people from the impact, particularly the weaker section, of rising prices.

Once again, I express my gratitude to the Members for their very valuable contributions. The situation is no doubt serious, but we need not be panicky. I do not hope that it would be possible to tackle the problems faced by the country by cooperation of all concerned.

20.46 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification under Customs Act

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : I beg to lay on the Table a copy each of Notification Nos. 246/83-Customs and 247/83-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 25th August, 1983 together with an explanatory memorandum regarding exemption to melting scrap of stainless steel from the whole of customs duty leviable thereon, under section 159 of the Customs Act, 1962. [Placed in Library. *See* No. LT-6949/83]

20.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 26, 1983/ Bhadra 4, 1905 (Saka).